● वर्ष-2
● अंक-182
रायपुर, गुरुवार
23 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।
समाचार पचीसा
राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmailĐcom

कोयला परिवहन पर रमन-भूपेश उलझे

कोल ब्लॉक परिवहन में करोड़ों की गड़बड़ी का मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया, जवाब से असंतुष्ट भाजपा बहिर्गमन

रायपुर। आज सदन में प्रश्नकाल में पूर्व व वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच प्रश्नों व जवाबों की झड़ी लग गई। दोनों एसईसीएल के क्षेत्र में कोयला परिवहन दर में फर्क के मामले में आमने सामने हुए। रमनसिंह ने आरोप लगाया कि मिली चार निविदा में दो किस आधार पर निरस्त किया गया। दरों में दोगुना ज्यादा दिया जा रहा है। बड़ा नुकसान प्रदेश को हो रहा है। एसईसीएल द्वारा अनुमोदित दरों को लागू करें तो काफी पैसा बचेगा। यह बड़ा घोटाला है। प्रति टन 210 ज्यादा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आपके कार्यकाल में ही ये नियम बने हैं, जिसके तहत ही कार्य हुआ है। खदानों के भीतर व बाहर अलग अलग रेट होते हैं। रमनसिंह ने इसे बडा घोटाला बताते हुए , इसमें सदन की समिति से जांच करने व टेंडर निरस्त करने की माँग की। बघेल ने इससे इनकार करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आपके बनाए नियमों के आधार पर ही काम कर रहे हैं। रमनसिंह ने पुनः अपनी मांग को दोहराया और निरस्त करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने मंडवा प्रोजेक्ट लगाया। आपने टेंडर की शर्तें बनाई। क्या आपको तब इस बात का ज्ञान नहीं था क्या ? रमनसिंह ने आरोप लगाया कि 2 निविदा को अपात्र कर एडजस्ट करके 212 रु.ज्यादा दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका केमिकल लोचा है। हम तो बता रहे हैं कि 8 रु. व 11 रु. टन में परिवहन कर रहे हैं। ये 211 रु.कहाँ से आ गया? 8 टेंडर फॉर्म लिए गए, 4 ने टेंडर भरे 2 अपात्र पाए गए। रमनसिंह ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि जांच विधायकों की समिति द्वारा करवा लेवें भविष्य के लिए अच्छा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके कार्यकाल में इसी बात पर आपके सामने गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। जांच की जरूरत नहीं समझी गई थी ,अब भी जरूरत नहीं है। रमनसिंह ने खुली चुनौती देते हुए कि आप परिवहन दर पर तुलना कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा आपकी बनाई शर्तों के नियम को हम झेल रहे हैं। जांच की हम कोई जरूरत नहीं समझते हैं। विपक्षी भाजपा सदस्यों ने हल्ला गुल्ला कर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया।

रमन सिंह – ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुगने दर पर टेंडर दिया गया. एसईसीएल का रेट है उससे कहीं ज्यादा है. अतिरिक्त पैसा कहां जा रहा है।

भूपेश बघेल– किलोमीटर के हिसाब से एसईसीएल खदान के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित है. जब पिछली सरकार में टेंडर किया गया और नियम बनाया गया उसी समय ये कह दिया जाता कि गाईडलाईन के हिसाब से परिवहन होगा, लेकिन साल 2017 में तो आपने ऐसा किया नहीं.

रमन सिंह – एसईसीएल ने नोटिफिकेशन जारी किया है इसे लेकर. कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए एसईसीएल मापदंड तय करता है. एसईसीएल जब गाईडलाईन तय कर चुका है, फिर छत्तीसगढ़ का उपक्रम क्यों रेट तय करेगा.

भूपेश बघेल – एसईसीएल कब से चल रहा है और उसके नियम भी पहले से बने हुए है. अलग-अलग जगह का अलग-रेट है. दूरी के हिसाब से किलोमीटर तय होता है. आपने नियम बनाया रहता तो टेंडर क्यों निकलता.

रमन सिंह – विधायकों की कमेटी से जांच हो, जब इतना बड़ा मामला है तो जांच क्यों नहीं.

भूपेश बघेल – हमने टेंडर के जरिये रेट तय किया है. 8 कंपनियां शामिल हुई टेंडर में. 4 लोग भरे थे टेंडर. जिसमें 2 पात्र पाए गए और 2 अपात्र पाए गए. ऑनलाइन टेंडर जारी किया,

रमन सिंह – मैं आपके चुनौती देता हूं कि 2012 के दर और अभी के दर पर खुली चर्चा करा लीजिए

भूपेश बघेल – पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है।

मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक सर्वसम्मति से पारित

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुप्रतीक्षित छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 बिना विपक्षी सदस्यों की चर्चा के सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। भाजपा सदस्यों अजय चंद्राकर व बृजमोहन अग्रवाल द्वारा प्रारम्भिक तकनीकी बातों का उल्लेख करते हुए बेहतर कानून बनाने के लिए इस विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप देने की मांग करते हुए कहा कि हमें इस विधेयक से कोई विरोध नहीं है। अच्छा कानून लाया जा रहा है। यह पत्रकारों के लिए अच्छा है। लेकिन हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं ना राह जाए यह सुनिश्चित होना चाहिए। अंततः मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव करने पर अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने विधेयक को नेता प्रतिपक्ष नारायण चन्देल की सहमति के साथ सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया। चर्चा व अवरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि आप लोगों ने 15 साल इस बात पर ध्यान दिया नहीं। हम कर रहे हैं तो आप अवरोध कर रहे हैं। आप क्या जवाब दे रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं।

इन दिनों

वनवासी या आदिवासी विकास तो हो

विधानसभा में जनजातीय विकास से जुड़े कुछ मामले चर्चा में आए। पहला विषय तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले लाभ से संबंधित था। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता तोड़ने वाले श्रमिकों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। इस मामले में यह भी जानकारी आई कि वर्तमान भूपेश सरकार ने तेंदूपत्ता तोड़ाई का पारिश्रमिक 2500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया है। लेकिन उससे तेंदूपत्ता तोड़ने वालों को जो लाभ मिलता था, वह कम हो गया है। विधानसभा में डॉ. रमन सिंह ने बताया कि 2017 में 17 लाख मानक बोरे तेंदूपत्ता का संग्रहण होता था और पारिश्रमिक व बोनस को मिलाकर 2017 में एक हजार 117 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, वहीं भूपेश सरकार ने वर्ष 2021 में 13 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया और पारिश्रमिक व बोनस मिलाकर कुल 630 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस हिसाब से पारिश्रमिक बढ़ाने के बावजूद तेंदूपत्ता तोड़ने वालों को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। पिछले 4 वर्षों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दूरी जनता के जेबों में अधिकाधिक पैसा डालने पर टिकी हुई है। भूपेश सरकार मानती है कि प्रति क्विंटल धान का पैसा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों की जेब में जा रहा है, गोबर खरीदने का पैसा भी गांव के लोगों की जेब में जा रहा है, यह पैसा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री थे कीन्स जिन्होंने लोगों के हाथों पैसा पहुंचाकर अर्थव्यवस्था बढ़ाने का सिद्धांत 1920 के दशक में दिया था। अब 2020 के दशक में यह सिद्धांत छत्तीसगढ़ में लागू हो रहा है। सवाल उठता है कि तेंदूपत्ता तोड़ने वालों की जेब में ज्यादा पैसा क्यों नहीं जा रहा है। विधानसभा में चर्चा के दौरान मंत्री कवासी लखमा ने इस बात पर आपत्ति की कि जनजातीय समुदाय के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि विधायक धर्मजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अपने जवाब में भी वनवासी शब्द का उल्लेख कर रही है। यह विषय जनजातीय समाज के बीच में बहुत तेजी से चर्चा में है कि उनके लिए वनवासी शब्द का प्रयोग न किया जाए। यही प्रश्न संविधान सभा में भी चर्चा के दौरान उठा था और आखिर में यह तय हुआ कि अनुसूचित जनजातीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तब से लेकर आज तक शब्द भले ही बदल गए हों, लेकिन वन क्षेत्रों में रहने वाले वनवासी हो या आदिवासी या जनजातीय इनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाई है। शब्द बदल लेने से आर्थिक और सामाजिक स्थिति नहीं बदलती उस समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए संबंधित प्रयास की आवश्यकता है।

ध्वस्त हुए माता शारदा मंदिर का हुआ पुनर्निर्माण

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में बदले माहौल में मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार तेजी से हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के आस्था स्थल जो दशकों से वीरान पड़े थे आज वहां रौनक लौट रही है और पूजा पाठ तथा हवन इत्यादि हो रहा है। आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शारदा के ऐतिहासिक मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस अवसर पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं जब भी जम्मू आऊंगा तो मेरी यात्रा की शुरुआत मंदिर के दर्शन के साथ होगी।

कुपवाड़ा में एलओसी के नजदीक टीटवाल गांव है जहां यह मंदिर स्थित है। सेव शारदा समिति की ओर से शारदा माता मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है। आज मंदिर के औपचारिक उद्घाटन से पहले मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी पूर्ण विधि विधान से की गयी। इस दौरान कश्मीरी पंडित तो बड़ी संख्या में उपस्थित थे ही साथ ही अन्य धर्मों के लोग भी मौजूद रहे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह मंदिर एलओसी के नजदीक है इसलिए जब सुबह शाम यहां आरती होगी और मंदिर की घंटियां बजेंगी और शंख ध्वनि गूंजेगी तो उसकी गूंज एलओसी के पार चिलियाना गांव तक

जायेगी।

हम आपको बता दें कि इस मंदिर के बारे में यह उल्लेख भी मिलता है कि 1947 से पहले इस स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हुआ करते थे। लेकिन कबायली हमले में इस टीटवाल गांव को जला दिया गया था। इसलिए सभी समुदायों के लोगों ने मिलकर एक शुरुआत की और फिर से धर्म स्थलों को बनवाया। हम आपको यह भी बता दें कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ ही अब कश्मीरी पंडितों की इच्छा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले शारदापीठ मंदिर की सदियों पुरानी तीर्थयात्रा फिर शुरू की जाये। माना जाता है कि शारदापीठ मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। जिस तरह कश्मीर में अमरनाथ मंदिर और मार्तंड सूर्य मंदिर का महत्व है उसी तरह शारदापीठ मंदिर भी हिंदुओं की गहरी आस्था का स्थल है।

हम आपको यह भी बता दें कि शारदापीठ मंदिर को मुगलों, अफगानों और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने काफी नुकसान पहुँचाया था। इस मंदिर की आखिरी बार मरम्मत 19वीं सदी के महाराजा गुलाब सिंह ने कराई थी। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कश्मीर में देवी की आराधना सबसे पहले शारदापीठ मंदिर में ही शुरू हुई थी बाद में खीर भवानी और माता वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई थी।

प्रमुख समाचार

दलितों पर अत्याचार- सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश आगे

नई दिल्ली। देशभर में चार वर्ष (2018-2021) में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 1.89 लाख मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 49,613 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर, जहां महज 14 फीसदी मामलों में ही दोष सिद्धि हुई और सजा दी गई। वहीं, उत्तर प्रदेश में 31 फीसदी मामलों में दोषसिद्धि हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश मिश्र की तरफ से देश में दलितों पर अत्याचार को लेकर पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-2021 के दौरान देश में दलितों पर अत्याचार के कुल 1,89,945 मामले दर्ज हुए। इनमें से 79 फीसदी मामलों में पुलिस ने अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए हैं। 27,754 मामलों में दोषसिद्धि हुई है। दोषसिद्धि के साथ ही उत्तर प्रदेश इस तरह के मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने के लिहाज से भी आगे हैं। यूपी में दर्ज 49,613 मामलों में से 41,684 (84 फीसदी) से ज्यादा मामलों में आरोपपत्र दाखिल हुए हैं। इसके अलावा 15,455 मामलों में दोषसिद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से मिश्रा ने बताया कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद दलितों पर अत्याचार के सबसे ज्यादा 26,815 मामले बिहार में दर्ज हुए हैं।

केंद्र से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा- जजों के नाम रोके जाने से वरिष्ठता प्रभावित होती है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से न्यायाधीशों की लंबित नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि न्यायाधीशों के नाम रोके जाने से उम्मीदवारों की वरिष्ठता प्रभावित होती है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए चार जिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। इसने आर शक्तिवेल, पी धनबल, चिन्नासामी कुमारप्पन और के राजशेखर के नामों की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि दोहराए गए नामों को रोकना या उनकी अनदेखी करना न्यायाधीशों की वरिष्ठता को परेशान करता है। इसने केंद्र को लंबित नियुक्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। संकल्प में कहा गया कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के संदर्भ में उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त नामित न्यायिक अधिकारियों की योग्यता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, इस कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श किया है।

भारत के कड़े जवाब से रास्ते पर आया ब्रिटेन, भारतीय उच्चायोग की बढ़ाई सुरक्षा

नई दिल्ली। ब्रिटेन सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों के विरोध से पहले लंदन में भारतीय मिशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। कुछ ब्रिटिश सिख समूहों द्वारा नियोजित प्रदर्शन के कारण बुधवार को यहां भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बता दें कि खालिस्तान समर्थकों ने रविवार को राजनयिक मिशन के ऊपर लहरा रहे तिरंगे को गिराने की कोशिश की और इमारत को तोड़ने का प्रयास किया। हमले के बाद, भारत ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को तलब किया और सुरक्षा की पूर्ण अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में बयान देते हुए कहा कि भारत ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति यूके सरकार की उदासीनता को अस्वीकार्य पाता है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ' ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। हालांकि, उच्चायोग की ओर जाने वाले रास्ते पर लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये आने-जाने में परेशानी पैदा कर रहे थे।

नौकरियों के घोटाले से 100 करोड़ रुपये पार्थ चटर्जी के पास गए

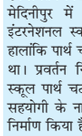

कोलकाता। पश्चिम बंगाल एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले से उत्पन्न 100 करोड़ रुपये से अधिक की आय बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की है। नई दिल्ली में एक विशेष पीएमएलए अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम के सहायक प्राधिकरण ने पुष्टि की। पीएमएलए के अधिनिर्णय प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय के निष्कर्षों की पुष्टि की जिसमें पाया गया कि अपराध की आय लगभग 100 करोड़ रुपये पार्थ चटर्जी की है। आय में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई 41 करोड़ रुपये की 40 अचल संपत्तियां शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में कृष्णाप्रिया में निर्मित बीसीएम इंटरनेशनल स्कूल को भी कुर्क कर लिया था, हालांकि पार्थ चटर्जी ने स्कूल पर दावा नहीं किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, बीसीएम स्कूल पार्थ चटर्जी का है, जिन्होंने अपने करीबी सहयोगी के नाम पर जिस जमीन पर स्कूल का निर्माण किया है, उसे खरीदा है।

राष्ट्रपति प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित

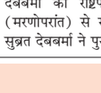

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा और प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोशी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण प्राप्त किया। कुमार मंगलम बिड़ला अपने परिवार में पद्म पुरस्कार पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। गायिका सुमन कल्याणपुर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण प्राप्त किया। पंडवानी गायिका उषा बारले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री प्राप्त किया। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया। माता नी पछेड़ी के 400 साल पुराने पारंपरिक शिल्प की विरासत को आगे बढ़ाने वाले चुनारा समुदाय के 7वीं पीढ़ी के कलमकारी कलाकार भानुभाई चित्रारा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री प्राप्त हुआ। त्रिपुरा के स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट के दिवंगत अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र देबबर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया। उनके बेटे सुब्रत देबबर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया।

भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों का गठबंधन मुश्किल

राजेश बादल

अगले लोकसभा निर्वाचन में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सरकार और विपक्षी दलों के लिए चुनावी तैयारी की घंटी बज गई है। पार्टियों के अंदर सुगबुगाहटें सियासी सरगर्मियों के तेज होने का संकेत देने लगी हैं। वैचारिक ध्रुवीकरण के चलते राजनीतिक दलों के दो खेमे साफ-साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी पार्टियों का और दूसरा कांग्रेस तथा उसके साथ समान वैचारिक आधार वाले दलों का है।

इसी बीच, कुछ क्षेत्रीय दलों ने भी दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से फासला बनाए रखते हुए तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। ये दल सिर्फ बड़े दलों से दूरी बनाए रखने के लिए गठबंधन संवाद कर रहे हैं। कोई तीसरी विचारधारा उनके पास नहीं है और न वे उसके आधार पर करीब आ रहे हैं। एक जमाने में वाम दल और समाजवादी पार्टियां सोच के आधार पर राष्ट्रीय परिदृश्य में उपस्थित थीं। लेकिन इन दिनों ये आधार भारतीय समाज से करीब-करीब गैरहाजिर हैं।

एक-दो दिन पहले बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव साझा मंच से लड़ने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी ने इसी मकसद से कोलकाता में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। दरअसल अखिलेश अभी भी अपना राजनीतिक चिंतन और सोच का दर्शन विकसित नहीं कर पाए हैं। पिता की विरासत तो उन्होंने संभाल ली, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जिस माहौल में अपनी समाजवादी सोच को परिपक्व किया था, वह अखिलेश को नहीं मिला। इसलिए राष्ट्र की समाजवादी जमीन के संस्कार स्वाभाविक ढंग से पल्लवित नहीं हो सके।

पिछले कुछ चुनाव इसका गवाह हैं। कभी वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो कभी बसपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। कभी

वे राष्ट्रीय जनता दल से प्रभावित दिखाई देते हैं तो कभी अचानक सबसे दूरी बना लेते हैं और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में नजर आते हैं।

जब राष्ट्रीय क्षितिज पर तीन दशक पुरानी एक पार्टी का मुखिया इतना अस्थिर हो तो उससे लोकतांत्रिक मजबूती के यज्ञ में आहुति की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। उन्हें आने वाले आम चुनाव के लिए विपक्षी एकता का सूत्रधार बताया जा रहा है, मगर यह सूत्रधार ठोस काम करेगा, इसमें संशय है। समाजवादी पार्टी को सूत्रधार की भूमिका सौंपने के बारे में भी अन्य पार्टियां एकमत नहीं हैं। अनेक दल अपने स्तर पर खुद को सूत्रधार के रूप में पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अगुआ नीतीश कुमार हैं। वे ऐलान कर चुके हैं कि भाजपा सरकार को शिकस्त देने के लिए विपक्षी अश्वमेध का घोड़ा लेकर चल रहे हैं। इसमें वे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के अलावा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) जैसी पार्टियों को अपने साथ मान रहे हैं। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के शिखर परिवारों में रिश्तेदारी भी है, इस कारण नीतीश समाजवादी पार्टी की संभावना अपने गठबंधन में देख रहे होंगे, मगर यदि अखिलेश ममता बनर्जी के पाले में हैं तो नीतीश कुमार के लिए कोई अवसर नहीं है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की अदावत सबको पता है।ममता कभी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मोर्चे में शामिल नहीं हो सकतीं। वे एक बार भाजपा के साथ जा सकती हैं, मगर जेडीयू के साथ उनका मेल संभव नहीं है। पर इस मोर्चे में ममता के शामिल होने पर कांग्रेस असहज रहेगी। ममता अनेक मौकों पर सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की खिल्ली उड़ा चुकी हैं। इस नजरिये से इस मोर्चे या गठबंधन की भ्रूणहत्या तय है। विपक्षी एकता के एक सूत्रधार के रूप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सर्वेसर्वा केसीआर भी अपने को सियासी मंच पर पेश कर चुके हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप देने का निर्णय लिया है। अब उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल है कि क्या वे अपने पड़ोसी प्रदेश आंध्र में सरकार चला रही वायएसआर से इस मामले में गले मिल सकते हैं? यह नामुमकिन सा है क्योंकि दोनों दलों के राजनीतिक हित एक-दूसरे के राज्य में टकराते हैं। क्या दो प्रतिद्वंद्वी पार्टियां अपने ही निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों पर तालमेल कर सकती हैं? ऐसी सूरत में केसीआर भी बेहद कमजोर सूत्रधार दिखाई देते हैं। अलबत्ता वे डीएमके के साथ जाकर कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके मोर्चे को या व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई शिखर भूमिका मिल सकेगी - इसमें संदेह है।यह दिलचस्प समीकरण है कि विपक्षी एकता के तीन सूत्रधारों के इस गठबंधन की व्यावहारिक उपयोगिता शून्य है। इसलिए कि इन सभी दलों का अस्तित्व उनके अपने अपने प्रदेशों से बाहर नहीं है। अगर उनके गठबंधन बनते भी हैं तो वे नहीं होने के बराबर हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का आपसी गठबंधन देखें तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से मिलकर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है? उसका तो कोई वोट बैंक ही वहां नहीं है। न ही ममता बनर्जी प्रयोग के तौर पर समाजवादी पार्टी को कोई लोकसभा सीट तालमेल के तहत दे सकती हैं।

भूकंप से सांसद बैज और अन्य कांग्रेसी सुरक्षित

झटके लगते ही फ्लैट से भागकर नीचे उतरे सांसद एवं कांग्रेसजन

जगदलपुर। बीती देर रात देश के अनेक भागों तथा पड़ोसी देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जिस समय भूकंप आया, उस समय बस्तर के कांग्रेस सांसद दीपक बैज नई दिल्ली स्थित अपने फ्लैट में मौजूद थे। नई दिल्ली गए बस्तर के छह कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्त्ता भी बैज के साथ उनके फ्लैट में ही थे। जैसे ही भूकंप का अहसास हुआ, बैज और सभी कांग्रेसजन दौड़ते हुए फ्लैट से नीचे उतर आए और सामने की सड़क पर पहुंचकर ही उन्होंने राहत की सांस ली।

इन दिनों संसद का बजट सत्र चल रहा है, लिहाजा बस्तर के सांसद दीपक बैज नई दिल्ली में ही ठहरे हुए हैं। मंगलवार की शाम बैज संसद की कार्यवाही में भाग लेने के बाद राममनोहर लोहिया अस्पताल के सामने गोमती अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में लौट गए। फ्लैट में बस्तर के कांग्रेस नेता अनुराग महतो, जॉर्ज टोप्पो, नीलम कश्यप, चैतराम कश्यप, सोनू कश्यप, बैज के गनमैन आदि रुके हुए थे। उन सभी साथ भोजन करने के बाद सांसद दीपक बैज बस्तर के राजनैतिक हालातों तथा अपने संसदीय क्षेत्र के गांवों की समस्याओं तथा ग्रामीणों की मांगों पर चर्चा करने में मशगूल हो गए। इसी बीच रात करीब सवा दस बजे अचानक फ्लैट में रखे सामान अहसास हिलने डुलने लगे। बैज को भूकंप आने का अहसास हो गया और वे तथा सभी कांग्रेसजन व गनमैन दौड़ते हुए सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर आए। दहशत ऐसी थी कि किसी को नीचे उतरने के लिए लिफ्ट का सहारा लेने के बारे में सूझा ही नहीं। अपार्टमेंट से भागते हुए बाहर निकलकर सांसद बैज और अन्य सभी लोग सड़क पर जा पहुंचे। वे आसपास की ईमारतों और पेड़ों से सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए। गोमती अपार्टमेंट तथा अन्य ईमारतों में रहने वाले लोग भी बाहर निकल आए थे। भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी और झटके लगभग 70 सेकंड तक महसूस किए जाते रहे। इस बीच बस्तर समेत अन्य स्थानों पर निवासरत सांसद बैज के शुभचिंतकों और कांग्रेस नेताओं ने न्यूज चैनलों के माध्यम से दिल्ली में भूकंप आने की जानकारी मिलते ही सांसद दीपक बैज को फोन कर उनका कुशलक्षेम पूछने लगे। बैज एक एक कर सभी का फोन अटैंड कर उन्हें अपनी और साथ मौजूद सभी लोगों के सकुशल होने की जानकारी देते रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केबिनेट मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव एवं जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा, चित्रकोट के विधायक राजमन बेंजाम, नारायणपुर के विधायक चंदन कश्यप, जगदलपुर नगर निगम की महापौर सफीरा साहू, नगर निगम सभापति कविता साहू समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने फोन के जरिए बैज का कुशलक्षेम पूछा।

मां दंतेश्वरी की कृपा है मुझ पर : बैज

सांसद दीपक बैज से सेलफोन पर इस संवाददाता ने देर रात चर्चा की और उनका कुशलक्षेम पूछा। बैज ने कहा - मां दंतेश्वरी हम आदिवासियों और बस्तर के लोगों की आराध्य देवी है। मैं मां दंतेश्वरी का उपासक हूं और उनकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहती है। मां दंतेश्वरी की कृपादृष्टि ने ही मुझे तथा मेरे साथियों को भूकंप की त्रासदी से बचा लिया। बैज ने कहा कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों तथा माता - बहनों का आशीर्वाद और स्नेह भी मेरे साथ है। इन सभी वजहों से हम लोगों को आंच तक नहीं आ पाई।

विशेष आराधना के साथ हुई घट स्थापना फिर जले ज्योतिकलश

रतनपुर। देवी आराधना के साथ ही नवसंवत्सर की भी शुरुआत हो गई है। मां महामाया देवी की मंदिर में बुधवार की सुबह 5 बजे माता का नव श्रृंगार किया गया। विशेष आराधना के साथ हुई घट स्थापना फिर जले ज्योतिकलश। मां महामाया देवी की पूजा देश के 51वीं शक्तिपीठ के रूप में होती है। यहां पूरे नौ दिनों तक नवरात्र पर्व की धूम रहेगी। इस बार देवी मंदिर में 25 हजार ज्योति कलश प्रज्जवलित की गई है। वहीं, लखनी देवी में जवारा कलश का विशेष महत्व है। यहां इनकी पूजा मां अन्नपूर्णा के रूप में की जाती है। यही वजह है कि 28 साल से मंदिर में ज्वारा कलश स्थापित किए जा रहे हैं।

चैत्र नवरात्रि पर्व पर इस बार रतनपुर स्थित प्रसिद्ध महामाया देवी मंदिर में पूरे नौ दिनों तक यहां शतचंडी यज्ञ के साथ ही जसगीत का आयोजन भी होगा। वहीं, सप्तमी पर्व की रात पदयात्री हजारों की संख्या में देवी दर्शन करने पहुंचेंगे। यहां नौ दिनों तक अह्वालुओं की भीड़ लगी रहेगी। यहां 31 हजार ज्योति कलश प्रज्जवलित करने का विश्व रिकॉर्ड भी है। पूरे नौ दिनों तक मंदिर में श्रद्धालु सुबह पांच बजे से रात 12 बजे तक दर्शन कर सकेंगे।

बुधवार की सुबह 5 बजे माता का नव श्रृंगार किया गया। उन्हें अभिषेक कराया गया। नए वस्त्र धारण कराए गए। स्वर्ण मुकुट व नथिया पहनाई गई। सुबह 7 बजे से घट स्थापना शुरू हुई। इसके बाद माता 9 दिन व रात पूजा की मुद्रा में रहेंगी। भक्त माता का दर्शन करेंगे। 9वें दिन माता का श्रृंगार होगा। देवी आराधना के साथ ही नवसंवत्सर की भी शुरुआत हो गई है। शुक्ल और ब्रह्म योग में पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की गई। इसके साथ ही घट स्थापना कर मनोकामना ज्योति प्रज्जवलित की गई। दुर्गा सप्तशती के अनुसार बुधवार को नवरात्र होने से माता का आगमन नौका पर होगा, जो फसल, धन-धान्य और विकास के लिए लाभदायक रहेगा।

कटघोरा में निकाली गई शोभायात्रा

कोरबा में चैत्र नवरात्र और हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 के आगमन की पूर्व संध्या को कटघोरा कस्बे में सर्व हिंदू समाज ने भव्य शोभायात्रा निकाली। भगवा ध्वज और आकर्षक झांकियों के साथ बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। भजन कीर्तन करते हुए लोगों ने नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा का समापन राधा सागर तालाब में 11 हजार दीपदान के साथ किया गया। चैत्र नवरात्र पर्व की शुरुआत हिंदू नव वर्ष प्रतिपदा से हो रही है।

विधायक रंजना साहू ने विधानसभा में पूछे कृषि और प्रधानमंत्री आवास से जुड़े सवाल

धमतरी। विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने क्षेत्र की जनहित मुद्दों को लगातार विधानसभा के पटल पर पर तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न के माध्यम से विभागीय मंत्री से सवाल दाग रही है। विधायक रंजना साहू ने जल संसाधन विभागीय मंत्री से प्रश्न पूछा कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा वित्त 1 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक विभागीय बजट सहित अन्य मदों से कुल कितने कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गई एवं कितने राशि भुगतान की गई? वर्ष भर जानकारी देवें? प्रश्नांश अवधि के बजट में शामिल ऐसे कितने स्वीकृत कार्य हैं जिनकी वित्तीय स्वीकृति निविदा प्रक्रिया लंबित है, जानकारी देवें? उक्त अवधि में स्वीकृत कितने कार्य समय अवधि के पश्चात भी अपूर्ण है? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? पूछे प्रश्न का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने बताया कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रश्नावधी में विभागीय बजट में कुल 8 कार्य, जिनकी कुल राशि 11638.47 लाख की स्वीकृति हुई हैं, जिसमें अभी तक किसी भी कार्य के लिए राशि भुगतान नहीं की गई है, अन्य मदो से मनरेगा मद के अंतर्गत कुल 31 कार्यों में राशि 784.88 लाख की राशि स्वीकृत हुए, जिनमें अब तक कुल 220.12 लाख का भुगतान किया गया, प्रश्नांश अवधि में बजट में शामिल कार्यों में स्वीकृत 8 कार्यों में से चार कार्य निविदा की प्रक्रिया में है सभी कार्य अप्रारंभ है, जिस पर विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा कि स्वीकृति आदेश के उपरांत 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य निविदा की प्रक्रिया में रहना और किसी भी कार्य का प्रारंभ ना होना यह राज्य सरकार की उदासीनता का परिणाम है, जिसके कारण विभिन्न समस्याएं क्षेत्रवासियों के हो रही है। इसी तरह विधायक रंजना साहू ने कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों के लिए कृषि यंत्र उपकरण में प्रदत अनुदान के संबंध में सवाल दागे। इसके साथ साथ विधायक ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति के संबंध में सवाल किए एवं धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्य की स्वीकृति एवं नियमित संधारण की अवधि की जानकारी सहित विभिन्न सवाल विधानसभा के पटल पर दागे।

वन विभाग को 800 करोड़ रूपए की राजस्व राशि की प्राप्ति

रायपुर। वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य 500 करोड़ रूपये के विरूद्ध लगभग 800 करोड़ रूपये की राजस्व राशि प्राप्त की गई, जो लक्ष्य से 160 प्रतिशत अधिक है। विभाग की कार्य कुशलता से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनक्षेत्र में स्थित खदानी काष्ठ से खनिज परिवहन हेतु टी.पी. शुल्क वसूली के प्रकरण में तत्परता दिखाते हुए 253 करोड़ रूपए की राशि वसूल कर शासन के राजस्व में जमा किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुसार कटाई किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में कुल 22 कार्य आयोजना प्रचलित वनमंडलों में एवं 01 वनमंडल की वर्किंग स्कीम की स्वीकृति कराकर इन वनमंडलों में विदोहन की स्वीकृति भारत सरकार से निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर विदोहन कार्य प्रारंभ किया गया। विदोहन से प्राप्त वनोपज का निर्धारित नीलाम से तिथियों में नीलाम से राजस्व वृद्धि हुई।

ट्रक-बस में भिड़ंत, आधे घंटे ट्रक में फंसा रहा चालक

ओवरटेक करने की चक्कर में हादसा

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बुधवार दोपहर एक ट्रक और बस की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने की चक्कर में तेज रफ्तार बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। इसके चलते ट्रक चालक केबिन में ही फंस गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। हादसे के बाद बस चालक भाग निकला है।

जानकारी के मुताबिक, पंडरिया से बस बुधवार को कवर्धा जा रही थी। चालक काफी तेज बस चला रहा था। दोपहर करीब 12 बजे वो नेशनल हाईवे पर ग्राम हरिनछपरा के पास पहुंची थी कि ओवरटेक करने की चक्कर में सामने से आ रही ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का शीशा टूट गया और वह ट्रक में जा घुसी। इसके चलते ट्रक का केबिन दब गया और चालक अंदर ही फंस गया। हादसे के समय बस में 30 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। टक्कर लगते ही चीख-पुकार मच गई।

सबसे ज्यादा चोट बस में सामने की ओर बैठे लोगों और ट्रक चालक को आई है। हादसा होते देख राहगीरों ने डायल 112 को सूचना दी। इसके बाद कवर्धा कोतवाली और पोंड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं ट्रक में फंसे चालक को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसका पैर टूट गया था और वह अंदर बुरी तरह से फंसा था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे बाहर निकाला। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कवर्धा से पोंड़ी रोड अब डेंजर जोन बन गई है। यह मार्ग नेशनल हाईवे में आता है, जो कि कवर्धा से जबलपुर तक है। ये सड़क छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से जोड़ती है। यही कारण है कि यहां ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव बना होता है। जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां हमेशा दुर्घटना होती रहती है। इस साल इसी सड़क पर अब तक अलग-अलग सड़क हादसे में चार लोगों की मौत भी हो चुकी है।

एटक का वार्षिक सम्मेलन संपन्न

कोरबा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक से संबद्ध एल्युमिनियम एम्पलाईज यूनियन एटक का वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य वक्ता एवं मार्गदर्शन के लिए छग राज्य एटक के अध्यक्ष कॉमरेड आरडीसीपी राव और राज्य एटक के महासचिव कॉमरेड हरिनाथ सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। दोपहर 2 बजे राज्य अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। यूनियन महासचिव ने वर्ष 2022 में मजदूर हित में हुए काम और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना हैए अपने प्रतिवेदन को सभी के सामने रखा। उन्होंने 11 मुद्दों पर पर एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की बात कही। प्रतिवेदन पर लगभग 25 लोगों ने अपना विचार रखा। सभी ने प्रतिवेदन का समर्थन करते हुए एटक को मजबूत करने पर जोर दिया। जिन मुद्दों को लेकर महासचिव ने आगे रणनीति बनाने के लिए कहाए उस पर सभी लोगों ने सहमति दी और कहा कि हम सब एक साथ मिलकर मजदूर हित में काम करेंगे। आने वाले समय में मजदूरों को जो भी नुकसान हुआ है और नुकसान भविष्य में न हो इसका ख्याल रखा जाएगा। अंत में पदाधिकारियों का चयन हुआ जिसमें अध्यक्ष एस.के.सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष एम.एल. रजक, उपाध्यक्ष हरिनाथ सिंह, लालमन सिंह, अनूप सिंह, रामायण यादव, महासचिव सुनील सिंह, सहायक महासचिव धर्मेंद्र सिंह, जी नरसिम्हा राव, सचिव जयराम कंवर, लालू राव, मनीष नाग, अविनाश सिंह, संगठन मंत्री धर्मेन्द्र तिवारी, कोषाध्यक्ष पी के वर्मा, आमंत्रित सदस्य में आलेख मल्लिक, ताराचंद कश्यप के अलावा कुल 101 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शाह सीआरपीएफ के राइजिंग समारोह में होंगे शामिल

बस्तर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। श्री शाह 24 मार्च की शाम जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से चलकर श्री शाह कारनपुर पहुंचेंगे जहां सीआरपीएफ कैंप में कोबरा बटालियन के जवानों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार, श्री शाह 24 मार्च से दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। शाम 5.20 बजे हेलीकॉप्टर से कारनपुर कोबरा सीआरपीएफकैंप जाएंगे और जवानों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 25 मार्च को सुबह 8 बजे से सीआरपीएफ के राइजिंग समारोह में भाग लेंगे। रात 8 बजे अधिकारियों के साथ नक्सल मुद्दे पर बैठक करेंगे और सीआरपीएफकैंप में ही रात बिताएंगे। अगली सुबह 11.45 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट से नागपुर के लिए रवाना होंगे।

25 हाथियों का दल जमकर मचा रहा उत्पात, झोपड़ी तोड़ा

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। जंगल के किनारे बने झोपड़ी को तहस-नहस किया। यह पूरा मामला वाड्फ्लगर वनपरिक्षेत्र के कोटराही बसरिया पारा का है। मिली जानकारी के अनुसार, तमोर पिंगला से आए हाथियों के दल ने कोटराही बसरिया पारा में जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि, लगभग 25 हाथियों का दल इलाके में विचरण कर रहा है। हाथियों ने जंगल के किनारे बने झोपड़ी को तबाह किया और वहां रखे महुआ और अनाज को भी चट कर दिया। मौके पर पहुंचे वन विभाग द्वारा इलाके में अलर्ट जारी किया गया है।

हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ग्राम पतोरा में संपन्न

पाटन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन के द्वारा ग्राम पतोरा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और ग्रामीणों से छत्तीसगढ़ सरकार के जनहितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। उक्त यात्रा में प्रमुख रूप से कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष अश्वनी साहू,अपेक्स बैंक के डायरेक्टर राकेश ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, यात्रा प्रभारी प्रभात वर्मा, जनपद उपाध्यक्ष देवेंद्र चंद्रवंशी, जनपद सदस्य खिलेश मारकंडे, जोन प्रभारी सालिक साहू, नरेश वास, भूषण कौशल, सुरेश कपूर, करण सिंह, यशवंत ठाकुर, गैंदलाल साहू, विक्की चंद्राकर, चित्रसेन कलिहारी, भोलू बंदे, रामकुमार बंदे, जगतपाल वास, भरोसा यादव, सुखदेव ठाकुर, सोहन पठारी, सरजू साहू, नरोत्तम साहू, मनोज साहू, अरुण ठाकुर, सदन, सुरेश ठाकुर, लक्की वास, प्रकाश साहू, शेखर बंदे, कमलकांत साहू आदि शामिल हुए।

भिलाई ननि कमिश्नर ने उप अभियंता को किया सस्पेंड

भिलाई। भिलाई नगर निगम अंतर्गत वार्ड 65 सेक्टर 7 में निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की दीवार गिरने के मामले में निगम कमिश्नर रोहित व्यास ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्य में लापरवाही बरतने वाली महिला सब इंजीनियर को सस्पेंड करते हुए ठेकेदार का अनुबंध और कार्य आदेश भी निरस्त कर दिया है। नगर निगम कमिश्नर ने दीवार गिरने के बाद एक टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए थे। जांच टीम की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य करा रही उप अभियंता श्वेता महेश्वरी को सस्पेंड कर दिया। वहीं, ठेकेदार का अनुबंध और कार्य आदेश निरस्त करते हुए अमानत राशि को राजसात करने के आदेश दिया है। कमिश्नर रोहित व्यास ने निर्माणाधीन इंडोर बैडमिंटन कोर्ट की दीवार गिरने के मामले में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया था। इस टीम ने इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया। टीम से मिली प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर निगमायुक्त ने सब इंजीनियर और ठेकेदार की गड़बड़ी पाई। जिसके बाद उप अभियंता श्वेता महिश्वर को निलंबित करने का आदेश जारी किया।

आयरन फैक्ट्री में आग, 2 घंटे में सात दमकलों ने पाया काबू

भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित एक आयरन फेरो फैक्ट्री में बुधवार दोपहर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू पाने के लिए सात दमकलों को दो घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान अंदर काम कर रहे मजदूरों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। आग से नुकसान का सही आकलन नहीं हो सका है। फिर भी करोड़ों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। मामला जामुल थाना क्षेत्र के छावनी इंडस्ट्रियल एरिया का है। जानकारी के मुताबिक, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में बंसल ब्रदर्स की फेरो एलॉय यूनिट है। इस फैक्ट्री में अत्याधिक ज्वलनशील पदार्थ टाइटेनियम के स्क्रैप को गलाने का काम किया जाता है। बुधवार को भी काम चल रहा था। इसी दौरान दोपहर को ओवर हीटिंग के चलते अचानक से आग लग गई और उसने विकराल रूप धारण कर लिया। अचानक से आग भड़की तो वहां काम कर रहे मजदूर किसी तरह से बचकर भागे और अपनी जान बचाई। आग से करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

चोर अंदर एटीएम काट रहे थे, बाहर पुलिस इंतजार कर रही थी

फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार हुए तीन शातिर

भिलाई। भिलाई कुम्हारी पुलिस ने नेशनल हाइवे के किनारे स्थित कपड़ा मार्केट के पास एचडीएफसी बैंक एटीएम काटकर चोरी कर रहे अंतर्राज्जीय गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों में दो नाबालिग शामिल हैं सभी आरोपी मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उनके पास से एक मोटर साइकिल, गैस कटर समेत अन्य सामान बरामद किया है।

कुम्हारी थाना प्रभारी सुधांशु बघेल ने बताया कि पेट्रोलिंग टीम देर रात गश्त कर रही थी। 21-22 मार्च की बीती रात करीब 3 बजे के आसपास पेट्रोलिंग टीम ने देखा कि एचडीएफसी बैंक के एटीएम का शटर नीचे से खुला हुआ है शक होने पर सिपाहियों ने नजदीक जाकर देखा तो एटीएम के पास एक बाइक खड़ी थी और अंदर कुछ लोगों के होने की आहट आई। इस दौरान एटीएम से सायरन बजने की आवाज आने लगी। पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत एटीएम की घेराबंदी की। जिससे आरोपी भागने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। पकड़े गए आरोपी एटीएम मशीन को गैस कटर की मदद से काट रहे थे। एटीएम मशीन में करीब 11 लाख रुपये कैश था। जिसे पुलिस ने आरोपियों के पास से रिकवर कर लिया।

टीम को आईजी ने की नगद इनाम देने की घोषणा

कुम्हारी थाना प्रभारी सुधांशु बघेल और उनकी टीम को कार्रवाई को देखते हुए आईजी आनंद छाबड़ा ने 10 हजार नगद राशि देने की घोषणा की है। कुम्हारी पुलिस ने इस बड़ी वारदात होने से पहले तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। संभावना जताई जा रही कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है।

अंबिकापुर शहर में घुसा जंगली सूअर दो महिलाओं पर किया हमला

अंबिकापुर। हाथी, भालू,बायसन के बाद अब जंगली सूअर भी अंबिकापुर शहर में घुसने लगे हैं। मंगलवार की सुबह जंगली सूअर के हमले से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई।दोनों महिलाएं मार्निंग वाक पर निकली थी। उसी दौरान जंगली सूअर ने महिलाओं पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों द्वारा शोर मचाने के बाद जंगली सूअर वहां से चला गया लेकिन उसके बाद से लोकेशन नहीं मिल रहा है।

वन विभाग की टीम जंगली सूअर की खोजबीन में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जंगली सूअर ,महामाया पहाड़ की ओर से भोर में ही शहर में घुस गया था। महामाया पहाड़ का हिस्सा लुचकी जंगल से लगा हुआ है। महामाया पहाड़ से निकलने के बाद जंगली सूअर सीधे रिंग रोड से लगे हरसागर तालाब के पास पहुंच गया। यहां एक महिला सुबह घूमने निकली थी। अचानक सूअर ने उस पर हमला कर दिया। महिला कुछ समझ पाती उसके पहले ही जंगली सूअर ने उसके शरीर पर कई स्थानों में काट कर जख्मी कर दिया। जब महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो आसपास लोग शोर मचाने लगा तब जंगली सूअर वहां से तेजी से भाग गया।वहां से जंगली सूअर सीधे चांदनी चौक की ओर बढ़ गया। यहां भी सूअर ने एक महिला पर हमला कर दिया।दो महिलाओं पर जंगली सूअर के हमले की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम ने जंगली सूअर की खोजबीन शुरू की। आसपास के क्षेत्र में लोगों को सतर्क करने के साथ उसकी खोजबीन शुरू की है लेकिन दो महिलाओं पर हमला कर जख्मी करने वाले जंगली सूअर का अब कुछ पता नहीं चल पा रहा है। संभावना है कि शहर के मायापुर, बौरीपारा क्षेत्र में ही सूअर कहीं छिप गया है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली के बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है : केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा में आज 2023-2024 का बजट पेश किया गया। बजट को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने कहा कि हम मुफ्त शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं देते रहे हैं, लेकिन कभी घाटा नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुफ्त की योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार-रोधी सभी उपाय, घर पर सेवाएं मुहैया कराना जारी रहेगा। केजरीवाल ने कहा कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्रों में भारी निवेश किया है, यह बजट 'स्वच्छ, सुंदर, आधुनिक दिल्ली' पर केंद्रित है। बजट पेश करने के बाद दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि किसी राज्य के पास इतनी व्यापक योजना नहीं है जहां बड़े से लेकर छोटे पहलुओं पर काम किया गया हो।

शारदा देवी मंदिर खोले जाने का महबूबा ने किया स्वागत

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के नजदीक स्थित शारदा देवी मंदिर को बुधवार को खोला गया। चैत्र नवरात्रि जिस दिन शुरू हो रहा है उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे खोला। इसको लेकर पीडीपी प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने शारदा देवी मंदिर खोले जाने के फैसले का स्वागत किया और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार बहाल होने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छा है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि संबंधों को बनाए रखने, लचीला रुख रखने और विवादों का समाधान करने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शारदा देवी मंदिर को खोलना अच्छी बात है। कश्मीरी पंडित भी इस मंदिर को दोबारा खुलवाना चाहते थे। अमित शाह ने कहा कि आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर शारदा माता के मंदिर को लोगों के लिए खोला जा रहा है।

गिरफ्तार सिख युवाओं को कानूनी मदद देगा अकाली दल

चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि उनकी पार्टी भगोड़े खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी सिख युवाओं को कानूनी सहायता प्रदान कराएगी। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने ट्विटर पर कहा, शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में चल रही अतिरिक्त संवैधानिक कार्रवाई में गिरफ्तार सभी सिख युवाओं को पूरी कानूनी सहायता प्रदान करने का फैसला किया है और यह सुनिश्चित किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा उनके अधिकारों को नहीं कुचला जाए। बादल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, शिरोमणि अकाली दल गैर-संवैधानिक तरीकों का सहारा लेकर केवल संदेह के आधार पर निर्दोष सिख युवाओं, विशेषकर अमृतधारी युवाओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता है। हम जारी कार्रवाई में गिरफ्तार सभी निर्दोषों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं।

कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस तरह एक बार फिर जमानत मिलने की सिसोदिया की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। इससे पहले मंगलवार, 21 मार्च को सिसोदिया पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर स्पेशल कोर्ट सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और कहा कि मनीष सिसोदिया द्वारा बार-बार फोन बदला जाना कोई मासूम कर्म नहीं, बल्कि यह साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया था। सीबीआई की तरफ से अदालत में पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपने फोन नष्ट कर दिए क्योंकि वह चैट नष्ट करना चाहते थे। ये एक गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

व्हाट्सएप के जरिए नीतीश को मिली जान से मारने की धमकी

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक उन्हें 36 घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गई थी। बिहार पुलिस ने इसको लेकर गुजरात क्राइम ब्रांच से मदद मांगी थी। बिहार पुलिस और गुजरात पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए गुजरात की एक क्राइम ब्रांच की टीम लगातार काम में जुटी हुई थी। फिलहाल आरोपी को गुजरात के सूरत से पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी का नाम अंकित मिश्रा है। वह 28 वर्ष का है। उसे फिलहाल बिहार लाने की कोशिश जारी है। पुलिस ने बताया कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद पटना पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6जी टेस्टबेड प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन

डिजिटल क्रांति में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि डिजिटल पावर देश के कोने कोने में पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 120 दिनों में 125 से ज्यादा शहरों में 5जी पहुंच चुका है। मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत डिजिटल क्रांति में काफी आगे बढ़ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री ने नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर और भारत के 6जी टेस्टबेड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज आईटीयू के एरिया ऑफिस, इनोवेशन सेंटर और साथ ही भारत के 6जी टेस्टबेड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। यह डिजिटल रूप से लाभकारी साबित होगा और इसके माध्यम से इनोवेशन के नए अवसर बनें।

मोदी ने कहा कि आज भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। भारत में हर महीने 800 करोड़ से अधिक यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट होते हैं। आज भारत में हर दिन 7 करोड़ ई-अथेंनटिफिकेशन होते हैं। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल इंडिया को एक नई ऊर्जा देने के साथ साउथ एशिया और ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान और नए इनोवेशन लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि विक्रम संवत 2080 के पहले दिन दूरसंचार, आईसीटी और संबंधित नवाचारों की शानदार शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि जब हम टेक्नॉलॉजिकल डिवाइड को ब्रिज करने की बात करते हैं तो भारत से अपेक्षा करना बहुत स्वाभाविक है। भारत का सामर्थ्य, भारत का इनोवेशन कल्चर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का स्किल्ड और इनोवेटिव मैनपावर, भारत का फेवरेबल पॉलिसी इनवायरमेंट सारी बातें इस अपेक्षा का आधार हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सफलता की कहानियों के कई अध्याय लिखे हैं। जैम ट्रिनिटी दुनिया के अध्ययन, शोध और विश्लेषण के लिए एक महान विषय है। भारत के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी केवल शक्ति का एक तरीका नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण का एक मिशन भी है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने डीबीटी के माध्यम से 28 लाख करोड़ रूपए से अधिक भारतीयों के खातों में भेजे हैं। जनधन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी अधिक बैंक खाते खोले हैं। आधार के द्वारा उन्हें अथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से अधिक लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया।

मोदी ने कहा कि अब भारत के गांवों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों में रहने वाले का प्रमाण है कि डिजिटल पावर कैसे देश के कोने-कोने में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बड़े पैमाने पर डिजिटल समावेशन को मजबूत होते देखा है। 2014 से पहले, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के केवल लगभग 6 करोड़ उपयोगकर्ता थे और आज यह संख्या लगभग 80 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि आज का भारत डिजिटल क्रांति के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5जी रोलआउट करने वाला देश है। केवल 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5जी रोलआउट हो चुका है। देश के करीब 350 नेटवर्क में 5जी सर्विस पहुंच गई है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की उच्चस्तरीय बैठक

देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अहम बैठक की। इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। जानकारी के मुताबिक, कोरोना के मामलों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी।

इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अपडेट किए गए आंकड़ों से पता चला कि भारत में 1134 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। मौजूदा वक्त में 7,026 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इस दौरान पांच लोगों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में एक-एक मौत की खबर है। इसके अलावा एक कोरोना संक्रमित की जान केरल में गई। देश में दैनिक सकारात्मकता 1.09 फीसदी दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता 0.98 प्रतिशत आंकी गई।

इससे पहले 16 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों को चिट्ठी लिखी थी। मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को चिट्ठी लिखकर कोरोना के प्रति सतर्क रहने को कहा था। मंत्रालय ने परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण और कोरोना से लड़ने के अनुरूप व्यवहार की रणनीति का पालन करने को कहा था। इन राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में सरकार से फाइव फोल्ड स्ट्रेटेजी के तहत हालात पर नजर रखने और जरूरी उपाय करने को कहा है।

केरल में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने बुधवार को सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि राज्य में मंगलवार को 172 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम जिलों में वायरस के मामले अधिक हैं। राज्य में फिलहाल 1,026 सक्रिय मामले हैं, इनमें 111 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। जिलों को निगरानी मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया है।

मोदी ने बिहार दिवस पर राज्य की जनता को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने अपनी लगन और कठिन परिश्रम से एक विशेष पहचान बनाई है तथा वे देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1912 में इसी दिन बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था।

कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने भाजपा पर किया प्रहार

जेपी नड्डा को राहुल से लगता है डर उनकी सादगी से भाजपा में खौफ

बेंगलरु। कर्नाटक में जमकर राजनीति हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं। इस सब के बीच कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने भाजपा पर प्रहार किया है। डीके शिवकुमार ने साफ तौर पर कहा कि मुझे लगता है कि जेपी नड्डा को राहुल गांधी से डर लगता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सादगी ने बीजेपी में खौफ पैदा कर दिया है। इसलिए वे आए दिन राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। वे उन पर अप्रत्यक्ष रूप से भी हमला कर रहे हैं। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक को भ्रष्टाचार की राजधानी बनाकर बहुत बड़ी गलती की है।

डीके शिवकुमार ने कहा कि वे भ्रष्टाचार के जरिए तमिलनाडु को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा था कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चहुंमुखी और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि कांग्रेस अब भी वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने में व्यस्त है और अपने नेता राहुल गांधी को बार-बार नए तरीके से पेश कर रही। कर्नाटक में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की 'विजय संकल्प यात्रा' के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि चुनावों में जीत हासिल करने में असमर्थ राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत में लोकतंत्र के खतरे में होने का आरोप लगा रहे हैं। केपीसीसी प्रमुख ने बाबूराव चिंचानसूर का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मछुआरा समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने परिषद के सदस्यों से इस्तीफा दे दिया है और कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं।

जेपीसी की मांग पर अड़ी कांग्रेस, मोदी चुप्पी तोड़िये : जयराम

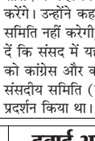

नईदिल्ली। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। अपने बयान में कांग्रेस नेता ने कहा कि जेपीसी का गठन 1992 में हुआ था जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, इसका गठन 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान भी हुआ था। दोनों शेयर बाजार घोटाले थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह घोटाला केवल शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पीएम मोदी और सरकार की नीतियों और इरादों से भी जुड़ा है। रमेश ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि अदानी चुप्पी तोड़िये। हम कह रहे हैं मोदी चुप्पी तोड़िये। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अडानी मामले में जांच के लिए जिस समिति का गठन हुआ है वे अडानी से सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो सवाल कर रहे हैं वे प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति नहीं करेगी, उनकी हिम्मत भी नहीं होगी। ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि संसद में यह मद्दा काफी गर्म है। इस मुद्दे को लेकर संसद में खूब हंगामा भी हो रहा है। मंगलवार को कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह के मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग करते हुए संसद भवन की पहली मंजिल के गलियारे में प्रदर्शन किया था।

खेल
प्रमुख समाचार

सरबजोत सिंह ने निशानेबाजी विश्व कप में एयर पिस्टल में स्वर्ण जीता

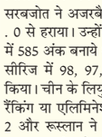

भोपाल। भारत के सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ पिस्टल राइफल विश्व कप में पुरूषों के एयर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों का खाता खोला। भारत के वरूण तोमर को भी कांस्य पदक मिला। दो साल पहले टीम और मिश्रित टीम वर्ग में जूनियर विश्व चैम्पियन रहे सरबजोत ने अजरबैजान के रूस्लान लुनेव को 16 . 0 से हराया। उन्होंने इससे पहले क्वालीफाइंग दौर में 585 अंक बनाये थे। सरबजोत ने क्वालीफिकेशन सीरिज में 98, 97, 99, 97, 97, 97 का स्कोर किया। चीन के लियु जिनयाओ दूसरे स्थान पर रहे। रैंकिंग या एलिमिनेशन दौर में सरबजोत ने 253 . 2 और रूस्लान ने 251 . 9 अंक बनाये। वरूण 250 . 3 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे।

भारत को 21 रन से हराकर आस्ट्रेलिया ने श्रृंखला जीती

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया ने एडम जम्पा (45 रन देकर चार विकेट) और एशटन एगर (41 रन देकर दो विकेट) की शानदार गेंदबाजी से भारत को महत्वपूर्ण मौकों पर झटके देकर बुधवार को यहां तीसरे और अंतिम वनडे में 21 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। भारतीय बल्लेबाजी फिर आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के दबाव में आ गयी और चेपक की धीमी पिच पर लक्ष्य का पीछा करते हुए 49.1 ओवर में 248 रन पर सिमट गयी। विराट कोहली (54 रन, 72 गेंद, दो चौके, एक छक्का) का अर्धशतक भी भारत को हार से नहीं बचा सका। आस्ट्रेलिया ने पहला वनडे पांच विकेट से गंवाने के बाद वापसी करते हुए लगातार दो वनडे में जीत दर्ज की। जम्पा ने भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। हार्दिक पंड्या के शानदार शुरूआती स्पैल और कुलदीप यादव की फिरकी ने आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर लगाम कसी लेकिन उसके पुछल्ले बल्लेबाजों ने 49 ओवर में सिमटने से पहले 269 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में मदद की।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 140 अंक चढ़ा निफ्टी 17,150 के पार

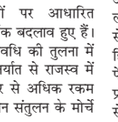

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज यानी बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 140 अंक मजबूत हुआ, वहीं निफ्टी 44 अंकों की बढ़त के साथ 17,150 के पार निकल गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 139.91 अंक यानी 0.24 फीसदी मजबूत होकर 58,214.59 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऊंचे में 58,418.78 तक गया और नीचे में 58,063.50 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 44.40 अंक यानी 0.26 फीसदी चढ़ा। निफ्टी कारोबार के अंत में 17,151.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ऊंचे में 17,207.25 तक गया और नीचे में 17,107.85 तक आया। आज के कारोबार में सेंसेक्स के शेयरों में 19 शेयर हरे निशान पर बंद हुए।

2023 के मध्य में लॉन्च हो सकते हैं चंद्रयान 3

नई दिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बुधवार को बताया कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 और पहले सोलर मिशन आदित्य एल1 को इसी साल के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। फिजिकल रिसर्च लैबोरेट्री द्वारा आयोजित चौथी इंडियन प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में इंडियन कैपेबिलिटीज फॉर स्पेस एंड प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन विषय पर बोलते हुए एस सोमनाथ ने यह जानकारी दी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। यह पूरी तरह से एकीकृत हो चुका है। हालांकि अभी कुछ काम किया जाना बाकी है लेकिन कई परीक्षणों के बाद हम मिशन को लेकर विश्वास से भरे हैं। इसरो चीफ ने कहा कि 2023 के मध्य में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है।

हवाई अड्डों का राजस्व अगले वित्त वर्ष तक बढ़कर 3.9 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान

नईदिल्ली। भारत में हवाई अड्डों के परिचालकों का राजस्व अगले वित्त वर्ष में 26 प्रतिशत बढ़कर 3.9 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। विमानन क्षेत्र की परामर्शदाता कंपनी कापा इंडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। हवाई अड्डों के लिए परिदृश्य पेश करते हुए कापा इंडिया ने कहा कि 2023-24 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालन में हवाई यात्री यातायात 39.5 करोड़ होने का अनुमान है। इसमें से, घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 27.5 करोड़ से बढ़कर इस वित्त वर्ष में 32 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या 5.8 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। कापा इंडिया ने कहा, 'ऐसा अनुमान है कि 2029-30 तक भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 70 करोड़ और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या 16 करोड़ पर पहुंच सकती है।'

इलेक्ट्रिक स्कूटर बिजनेस को बढ़ाने 300 मिलियन डॉलर जुटाएगी ओला इलेक्ट्रिक

नईदिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक भारत में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 300 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 24 अरब रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रही है। ये रकम ओला पश्चिम एशियाई और यूएस-आधारित वैश्विक निजी इक्विटी फंड से जुटाने की तैयारी कर रही है। वहीं इस डील से जुड़े सूत्रों की मानें तो कंपनी के इस कदम से प्रमोटरों की कंपनी के शेयरों की हिस्सेदारी घटकर करीब 37-38 फीसदी रह जाएगी जो कि मौजूदा समय में 40 फीसदी है। बता दें कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये फ्रेश राउंड फंडरेजिंग कर रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि ओला 300 मिलियन डॉलर की इस डील को जल्द ही पूरा कर लेगी।

भारत को निर्यात से मिलती राहत की गुंजाइश

प्रांजुल भंडारी, आयुषी चौधरी

भारत की सेवाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था में कुछ सार्थक बदलाव हुए हैं। महामारी से पहले की अवधि की तुलना में शुद्ध आधार पर, सेवा निर्यात से राजस्व में प्रति वर्ष 60 अरब डॉलर से अधिक रकम मिल रही है। इससे भुगतान संतुलन के मोर्चे पर काफी राहत मिली है।

सिर्फ मुद्रास्फीति ही इन आंकड़ों को बढ़ा रही है, ऐसा नहीं है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक सेवाओं के निर्यात ने उच्च तकनीक, मध्यम तकनीक और कम तकनीक वाली वस्तुओं के निर्यात को बड़े अंतर के साथ पीछे छोड़ दिया है। वास्तव में, भारत के सेवा क्षेत्र ने वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी हासिल करना जारी रखा है, भले ही वस्तुओं की हिस्सेदारी का स्तर सपाट ही रहा।

विश्लेषण से अंदाजा मिलता है कि आईटी सेवाओं की कुल सेवा निर्यात में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आईटी सेवाओं के निर्यात में, कंप्यूटर सेवाओं की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत है और इसके बाद पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं (22 प्रतिशत), तकनीकी और व्यापार से संबंधित सेवाएं (8 प्रतिशत) और अनुसंधान और विकास (3 प्रतिशत) की हिस्सेदारी है। संभवत: इस तरह की हिस्सेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों में वृद्धि के रुझान होना।

पिछले तीन वर्षों में, पेशेवर और प्रबंधन परामर्श क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ा है और इसमें 29 प्रतिशत की सलाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि हुई है और इसके बाद कंप्यूटर सेवाओं (16 प्रतिशत) तथा अनुसंधान एवं विकास (13 प्रतिशत) का स्थान है। एक क्षेत्र जो इन प्रमुख क्षेत्रों में से प्रत्येक के माध्यम से राजस्व बढ़ाता है, वह है

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और उसका उभार। हमारा भी मानना है कि आईटी सेवाओं में तेजी से वृद्धि में इसका योगदान है।

आखिरी जीसीसी क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें, तो वे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा भारत में स्थापित की गई इकाइयां हैं जो उन्हें वैश्विक तकनीकी सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास, इंजीनियरिंग और आईटी से संबंधित मदद देती हैं। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में जीसीसी स्थापित किए हैं और यह संख्या वित्त वर्ष 2015 के 1,026 से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 1,570 हो गई है। वास्तव में, भारत में लगभग 40 प्रतिशत वैश्विक जीसीसी हैं और इस अनुपात में विस्तार हो रहा है।

वर्तमान में इनका प्रत्यक्ष उत्पादन लगभग 51 अरब डॉलर के दायरे में है जो कुल आईटी सेवा निर्यात का 25 प्रतिशत है। पिछले दो वर्षों (वित्त वर्ष 2021-23) में जीसीसी के उत्पादन में 19 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है जो सामान्यतौर पर समग्र आईटी सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के अनुरूप है। अगले दो वर्षों के बाद, आईटी सेवाओं के लिए मध्यम अवधि का दृष्टिकोण पहले की तुलना में अधिक उत्साह से भरा दिखता है क्योंकि उद्योगों में तकनीक की पैठ है और जीसीसी से संभावनाओं के दायरे का विस्तार होता है।

भारत के तकनीकी व्यापार समूह नैसकॉम ने वित्त वर्ष 2030 तक आईटी सेवा राजस्व में 500 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। हमारा अनुमान है कि अगले दो साल में कुल सेवा निर्यात वृद्धि में अस्थायी नरमी के बाद वित्त वर्ष 2026 से 2030 के बीच इसमें करीब 9 प्रतिशत सीएजीआर तक की वृद्धि की दरकार होगी।

इससे भी दिलचस्प बात यह है कि शुद्ध आधार पर, निर्यात वित्त वर्ष 2019 के 6.8 अरब डॉलर प्रति माह से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 12 अरब डॉलर प्रति माह हो गया है और यह वित्त वर्ष 2030 तक 20 अरब डॉलर प्रति माह तक हो सकता है। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है कि वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2023 के बीच इसे 60 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिला है। अगर नैसकॉम का लक्ष्य हासिल हुआ तो वित्त वर्ष 2023 से 2030 के बीच शुद्ध सेवा निर्यात में 100 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है।

सीधे संघर्ष के करीब पहुँच गये अमेरिका और रूस?

नीरज कुमार दुबे

14 मार्च, 2023 को एक अमेरिकी ड्रोन रूसी विमान के साथ मुठभेड़ के बाद काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आकाश में हुई इस घटना ने जमीन पर दो बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच सीधी भिड़ंत की संभावनाओं और आशंकाओं को बढ़ा दिया है। हम आपको बता दें कि इस सप्ताह अमेरिका का निशस्त्र एमक्यू-9 निगरानी ड्रोन अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में जब उड़ान भर रहा था तब दो रूसी लड़ाकू जेट विमानों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का नया सिलसिला शुरू हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि अमेरिकी ड्रोन अपने ट्रांसपोंडर के साथ रूस की सीमाओं की दिशा में उड़ रहा था। रूस का कहना है कि उसने उड़ान को संदिग्ध पाया क्योंकि अमेरिकी ड्रोन ने अस्थायी सीमाओं का उल्लंघन किया।

दूसरी ओर, इस घटना को लेकर अमेरिका और रूस की प्रतिक्रियाओं के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रकरण अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में विमान और ड्रोन संचालित करने के देशों के अधिकार के मुद्दे को गर्माता है। यदि अमेरिकी पक्ष सही है तो रूस ने वास्तव में अमेरिकी ड्रोन के रास्ते में आकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। हम आपको बता दें कि समुद्र से जुड़े कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुच्छेद 87 के तहत, वह जलक्षेत्र जो किसी भी देश के क्षेत्रीय समुद्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं हैं- वह सभी देशों के लिए खुले हैं और किसी भी देश को इस क्षेत्र में उड़ान भरने की स्वतंत्रता हासिल है। अमेरिका हालांकि 1982 में की गयी इस संधि का पक्ष नहीं है लेकिन रूस सहित 168 देश इसके सदस्य हैं। फिर भी, अमेरिका इस कानून के कई प्रावधानों को मान्यता देता है। इसलिए अमेरिका का मानना है कि उसके अधिकार क्षेत्र में रूस ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया और यह कृत्य अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। दूसरी तरफ, रूस की चिंता यह है कि अमेरिकी ड्रोन उसके सैन्य अभियानों की जासूसी कर सकता था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर कोई नियम मानने को तैयार नहीं है। दरअसल कानून के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के भीतर रहते हुए दूसरे देश के क्षेत्र के भीतर निगरानी गलत नहीं है। अमेरिका इसी बात का फायदा उठाना चाहता है और रूस ऐसा नहीं होने देने के लिए कमर कस चुका है। वैसे, इस पूरे घटनाक्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रूस यह मानकर चल रहा है कि वह यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान के लिए नये सिरे से अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ स्थापित करने का हकदार था लेकिन अमेरिका ने उन सीमाओं की अवहेलना की। दरअसल रूस ने फरवरी 2022 में काला सागर के उत्तर-पश्चिम भाग में नेविगेशन को प्रतिबंधित करने के लिए समुद्री बहिष्करण क्षेत्र स्थापित किया था। अमेरिका ने भी इराक पर आक्रमण के सिलसिले में 2003 में भूमध्य सागर में एक समुद्री सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया था। लेकिन इस सबके बावजूद रूस के पास अमेरिकी ड्रोन के खिलाफ बल प्रयोग करने या हस्तक्षेप करने का एक उचित आधार केवल तभी होता जब यह ड्रोन सशस्त्र हमले का एक खतरा पैदा करता या वह किसी लक्ष्य पर हमला करने के लिए भेजा गया होता। वैसे भी यह एमक्यू-9 ड्रोन था जोकि निशस्त्र था। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है कि किसी देश ने अमेरिकी या अन्य किसी देश के निगरानी विमान की राह में बाधा पहुँचाई है और इसे मार गिराया है। 2001 में एक चीनी लड़ाकू विमान चीन के हैनान द्वीप से 70 मील की दूरी पर उड़ रहे अमेरिकी सिग्नल खुफिया विमान से टकरा गया था। अमेरिकी विमान को इस तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया कि उसे हैनान पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी, जबकि चीनी लड़ाकू विमान खुद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके अलावा चीन ने ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई विमानों को भी रोका था जो अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में नियमित निगरानी कर रहे थे।

दक्षिण की सियासत के पेच

आर. राजगोपालन

दक्षिण भारत की राजनीति में जातियों का बोलबाला रहता है। वोक्कालिगा, लिंगायत, रेड्डी, कम्मा, गौडा, थेवर, नाडार और एझवा नामक आठ बड़ी जातियों का दक्षिण भारत के छह राज्यों की राजनीति में वर्चस्व है। इसलिए दक्षिण की राजनीति को समझने से पहले इन बड़ी जातियों के सामाजिक दबदबे को समझना जरूरी है। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग ने उत्तर भारत में तो काम किया है, लेकिन दक्षिण में अमित शाह की चाणक्य नीति के समक्ष बड़ी बाधा है। ऑस्कर जीतने वाली फिल्म आरआरआर के गीत नाटु नाटु का भी एक सामाजिक ताना-बाना है। निश्चित रूप से यह गीत दक्षिणी राज्यों को आपस में जोड़ता है।

हालांकि दक्षिणी राज्यों को साधने के लिए भाजपा तत्परता से लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी उदारता से एक तेलुगू विद्वान को राज्यसभा के लिए मनोनीत करवाया। 35 से 40 फीसदी पद्म अवार्ड दक्षिणी राज्यों के लोगों को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले अपने %मन की बात% के 100 एपिसोड में 65 बार दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया। ये सब क्या दर्शाते हैं? जाहिर है, दक्षिण को गले लगाने की उत्तर भारतीय राजनेता की उत्सुकता को ही दर्शाते हैं। लेकिन क्या दक्षिण भारतीय मतदाता इन इशारों को स्वीकार करेंगे?

त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों को जीतने में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने प्रभावी ढंग से काम किया। लेकिन दक्षिणी राज्यों में मोदी का जादू केवल कर्नाटक और पुदुचेरी में ही देखा जा सकता है। दक्षिण में हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं है। अन्य तीन राज्य-आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भाजपा की सरकार नहीं है। इसलिए मोदी इसे तोड़ना चाहते हैं। दक्षिण भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भाजपा ने वाराणसी और सौराष्ट्र में तमिल संगमम आयोजित किया।

तमिलनाडु में द्रमुक सत्ता में है। राज्य में बिहारी प्रवासियों का मुद्दा भी बहस का विषय बना हुआ है। यह काफी संवेदनशील मुद्दा है। एक चिंगारी एकता के ताने-बाने को खत्म कर सकती है। मार्च की शुरुआत में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पर्दे के पीछे त्वरित कार्रवाई करके द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन के साथ बिहार एवं झारखंड के प्रवासियों के मुद्दे को प्रभावी ढंग से निपटाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके समाधान में शामिल रहे। इन तीनों प्रमुख नेताओं के बीच समन्वय का काम सक्षम नौकरशाही ने किया।

इसी तरह हिंदू धर्म से ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में चुपचाप हो रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने गृह मंत्रालय को भेजी अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। तीसरी और सबसे खतरनाक घटना दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और एसडीपीआई की गतिविधियां हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दोनों राज्यों में कम से कम 45 जगहों पर बार-बार की गई छापेमारी ने प्रभावी रूप से पीएफआई की नीतियों के प्रसार पर रोक लगा दिया।

आंध्र प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है। लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता जगन रेड्डी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के काफी करीब हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) है। इसके नेता चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में लौटने के लिए बेताब हैं। कांग्रेस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं नहीं है। तेलुगू भाषी राज्यों को बांटकर कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद खोद ली।

जहां तक चंद्रशेखर राव की बात है, तो उनके द्वारा शासित राज्य तेलंगाना भी अस्थिर है। दक्षिणी राज्यों की शराब लॉबी ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टीआरएस, अब बीआरएस) की छवि खराब की। आम आदमी पार्टी के साथ टीआरएस का अनोखा गठजोड़ कहीं ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली- तेलंगाना की हॉट लाइन राजनीति में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की नेता कविता की जोड़ी के उदय ने इन दोनों के राजनीतिक भविष्य को खराब कर दिया। कविता बहुत चतुर महिला राजनेत्री हैं। दक्षिण भारत के नेताओं के परिजनों ने अपने पिता और पार्टियों की छवि खराब की है। के चंद्रशेखर राव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। लेकिन अगले एक दशक तक भाजपा या मोदी दक्षिण में चाहे जितनी भी पहुंच बना लें, वांछित राजनीतिक नतीजा नहीं मिलेगा। अभी सियासी लोहा उतना गर्म नहीं हुआ है कि उस पर चोट की जाए। दक्षिण भारत के सभी राज्य अनूठे हैं।

अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे भाजपा के तीन शीर्ष नेताओं ने छह दक्षिणी राज्यों को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके कदम फिसलन भरे थे। केंद्रीय बजट में दक्षिण भारतीय राज्यों को भारी धन आवंटन, बुनियादी ढांचा, रक्षा गलियारा, जीएसटी परिषद की भागीदारी और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उपग्रह प्रक्षेपणों का निजीकरण-मोदी सरकार के कुछ प्रमुख कदम हैं। प्रमुख स्टार्ट-अप केवल दक्षिणी राज्यों में हैं।

बिना राजनीतिक खेल के आप दक्षिण भारतीय लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं। सिने जगत की कद्दावर हस्ती-एमजीआर, एनटी रामा राव, जयललिता और कर्नाटक के राजकुमार यहां के बड़े राजनेता रहे हैं। चुनावों को लेकर आप जो भी कयास लगाएं, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों, खासकर तमिलनाडु और केरल के मतदाता चुनावों के दौरान मौद्रिक लाभ की उम्मीद करते हैं। चुनावों के दौरान हर मतदाता को सत्ताधारी दलों और विपक्ष की ओर से 25 से 30 हजार रुपये तक मिल जाते हैं। दक्षिण में चुनाव का यह भी एक पहलू है। दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्तर-दक्षिण का भेदभाव गहरा है, खासकर तमिलनाडु में। ऐसा क्यों है और क्या इससे राजनीति प्रभावित नहीं होती है? कर्नाटक विधानसभा के चुनाव मुख्यधारा की राष्ट्रीय राजनीति के भविष्य का खुलासा करेंगे। कर्नाटक के नतीजे इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे कि क्या दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी को गले लगाता है या क्षेत्रीयता को तवज्जो देता है?

प्रसंग

सच्चा देशभक्त

सन् 1761 में अहमदशाह दुर्रानी ने अफगानी सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया। शत्रु से लोहा लेने के लिए मराठा सेना आगे बढ़ी, जिसका प्रधान सेनापति था। सदाशिव भाऊ पेशवा दोनों सेनाएँ पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आमने-सामने आ डटीं । दुर्रानी रुक गया और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन दुर्रानी को एक ऊंचे टीले से यह दिखाई दिया कि भारतीय सेना के पड़ाव के चारों ओर धुआँ छाया हुआ है। उसने इस बाबत जब अपने साथियों से प्रश्न किया, तो एक ने जवाब दिया, हिन्दू लोगों का एक साथ भोजन नहीं बनता, क्योंकि वे दूसरों के हाथ का बनाया खाना नहीं खाते, इसीलिए सब सिपाही कपड़े उतारकर अपना-अपना खाना पका रहे हैं। दुर्रानी बोला, बस, यही अच्छा मौका है, धावा बोल दो ।

सेनापति की आज्ञा मिलते ही अफगानी सेना मराठों पर टूट पड़ी, जिससे चारों ओर खलबली मच गयी। यद्यपि मराठों ने मुकाबला किया, किन्तु अन्त में वे पराजित हुए। अफगानों ने हजारों भारतीय सैनिकों को बन्दी बनाकर उन्हें निर्दयतापूर्वक मारना आरम्भ किया। उन बन्दियों में इब्राहिम खाँ गारडी नामक एक मुसलमान सरदार भी था। उसे भी पकड़कर दुर्रानी के पास लाया गया। दुर्रानी उससे बोला, तुम तो बड़े ही सूरमा मालूम पड़ते हो। यदि हमारी सेना में भर्ती होकर हिन्दुस्तान को लूटने में सहायता करोगे, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1910 डॉ राममनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में हुआ था।
1956 पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र बना।
1965 नासा ने पहली बार जैमिनी 3 अंतरिक्ष यान से दो व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा।
1976 मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का जन्म नई दिल्ली में हुआ था।
1983 अमरीका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने स्ट्रैटेजिक डिफ़ेंस इनीशियेटिव या रणनीतिक रक्षा प्रबंध की घोषणा की।
1986 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की पहली कंपनी को प्रशिक्षित किया गया।
1987 पश्चिमी जर्मनी के एक ब्रितानी सैनिक ठिकाने में हुए कार बम हमले में 31 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट इतना भयानक था कि सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई और पास में खड़ी कारों को काफ़ी बुरी तरह नुक़सान पहुँचा।
1996 ताइवान में हुए पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें ली टेंग हुई को बतौर राष्ट्रपति चुना गया।
2012 मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का कीर्तिमान बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

याज्ञवल्क्यापनिषद् (भाग-01)

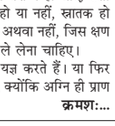

यह उपनिषद् शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद वर्णित है, जिसमें संन्यास धर्म की विस्तृत विवेचना हुई है। संन्यास धर्म की जिज्ञासा रखने वाले राजा जनक से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तथा वानप्रस्थ के बाद संन्यास का क्रम है; किन्तु भावप्रवणता की स्थिति में वैराग्य भाव की प्रचुरता की स्थिति में कभी भी संन्यास लिया जा सकता है। संन्यास ग्रहण करने वाले को शिखा, यज्ञोपवीत आदि के त्याग का विधान है। यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा? इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ?कार ही संन्यासी का यज्ञोपवीत होता है। आगे क्रमशः संन्यासी के गुणों, आचार-विचार आदि की विस्तृत चर्चा है। साथ ही संन्यासी को उसके पथ से विचलित करने वाली स्त्री के दोषों का बीभत्स चित्रण भी किया गया है। सन्तान भी दुःखदायी है - यह कहते हुए संन्यासी को लोभ, मोह, काम-क्रोध से बचने का निर्देश है। अन्त में संन्यासी को जितेन्द्रिय बने रहने की सलाह देते हुए उसे अपने एक मात्र लक्ष्य परब्रह्म के चिन्तन-मनन करने का निर्देश है, क्योंकि इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होना सम्भव है।

एक समय विदेहराज जनक महर्षि याज्ञवल्क्य जी के समक्ष जाकर बोले- हे भगवन्! आप कृपा करके हमें संन्यास धर्म समझाने का कष्ट करें। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा- हे राजन! ब्रह्मचर्याश्रम को विधि-विधान से पूर्ण करके, गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में पुत्र - कलत्रादि का सुख भोगकर वन में निवास करे। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम को धारण कर लेना चाहिए। यदि जितेन्द्रिय हो जाये, तो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ले ले या फिर अपनी इच्छानुसार गृहस्थ आश्रम के पश्चात् ले लेना चाहिए। वस्तुतः वानप्रस्थ के पश्चात् या फिर जिस दिन संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाए, उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए। चाहे व्रती हो या नहीं, स्नातक हो अथवा न हो, अग्नि की सेवा कर चुका हो अथवा नहीं, जिस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए।

इसके पश्चात् कुछ लोग प्राजापत्य यज्ञ करते हैं। या फिर इस यज्ञ को न कर आग्नेय यज्ञ ही कर ले, क्योंकि अग्नि ही प्राण है।

क्रमशः...

भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस

भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देशप्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। 23 मार्च यानि, देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते-हंसते न्यौछावर करने वाले तीन वीर सपूतों का शहीद दिवस। यह दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने वा गौरव का अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है।

उन अमर क्रांतिकारियों के बारे में आम मनुष्य की वैचारिक टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है। उनके उज्ज्वल चरित्रों को बस याद किया जा सकता है कि ऐसे मानव भी इस दुनिया में हुए हैं, जिनके आचरण किंवदंति हैं। भगतसिंह ने अपने अति संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति की जो मशाल जलाई, उनके बाद अब किसी के लिए संभव न होगी।

आदमी को मारा जा सकता है उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगतसिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह लिखा था।

भगतसिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून-खराबा न हो तथा अंग्रेजों तक उनकी आवाज पहुंचे। निर्धारित योजना के अनुसार भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेम्बली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी साण्डर्स की हत्या में भी शामिल होने के कारण देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला। यह मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है।

भगतसिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को शाम 7.23 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई।

शहीद सुखदेवः सुखदेव का जन्म 15 मई, 1907 को पंजाब को लायलपुर पाकिस्तान में हुआ। भगतसिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में पास-पास ही रहने से इन दोनों वीरों में गहरी दोस्ती थी, सांडर्स हत्याकांड में इन्होंने भगतसिंह तथा राजगुरु का साथ दिया था।

शहीद राजगुरुः 24 अगस्त, 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में राजगुरु का जन्म हुआ। शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी प्रभावित थे।

पंजाब से निकलते चिंताजनक संकेत

डॉ धनंजय त्रिपाठी

पिछले कुछ महीनों से पंजाब में अलगाववाद और अस्थिरता को लेकर जो चिंताएं पैदा हुई हैं, उनका समाधान बहुत गंभीरता से करना होगा। यह महज संयोग नहीं है कि एक ओर पंजाब में अमृतपाल सिंह की सक्रियता बढ़ती है, तो दूसरी ओर दुनिया के अनेक देशों में खालिस्तान समर्थक उग्र प्रदर्शन होने लगते हैं। हालिया घटनाक्रम इंगित करते हैं कि यह सब कुछ सुनियोजित ढंग से हो रहा है तथा इसे हवा देने में विदेशी शक्तियां भी शामिल हैं।

यह जगजाहिर तथ्य है कि अस्सी-नब्बे के दशक में पंजाब में जो हिंसा और आतंक का दौर चला, उसमें पाकिस्तान की बड़ी भूमिका थी। अनेक आतंकियों को पाकिस्तान ने अपने यहां पनाह भी दी है। लंदन में भारतीय उच्चायोग से खालिस्तान समर्थकों द्वारा राष्ट्रीय झंडे को हटाने के कृत्य की जितनी भर्त्सना की जाए, कम है। भारत ने इस घटना पर अपना ठोस प्रतिवाद दर्ज कराया है और ब्रिटिश उच्चायोग की ओर से इसके लिए खेद भी व्यक्त किया गया है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली आदि देशों में कई महीनों से आक्रामक प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं। ऐसे में लंदन की घटना को एक आम घटना समझना हमारी भूल होगी। किसी देश का उच्चायोग या दूतावास एक संप्रभु स्थान होता है तथा स्थानीय पुलिस को भी उसके भीतर जाने की अनुमति नहीं होती है। उग्र प्रदर्शनकारियों को भवन से पहले रोका जाना चाहिए था। यह प्रश्न भी है कि आखिर ब्रिटिश सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनसे संकेत

मिलता है कि अमृतपाल सिंह के तार पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से पंजाब में जो कार्रवाई चल रही है और धर-पकड़ हो रही है, वह सराहनीय है। पर यह सवाल भी अहम है कि आखिर इतने समय से पुलिस और अन्य एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रहीं। जैसे ही पंजाब में अमृतपाल सिंह की सक्रियता बढ़ी और विदेशों में खालिस्तान समर्थक गुटों ने शोर करना शुरू किया, वैसे ही एजेंसियों को जांच-पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए थी।

बहरहाल, कुछ देर से ही सही, कार्रवाई हो रही है। हमें उम्मीद है कि जांच से पूरी तस्वीर साफ होगी। अपने देश में भी और दुनिया में अन्यत्र भी, आतंकवादी और अलगाववादी गुटों का करीबी रिश्ता नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोहों तथा हवाला कारोबारियों से होता है। पंजाब में नशीले पदार्थों का मसला तो गंभीर है ही, पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के भी मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में हिंसा और अस्थिरता को रोकना पुलिस और अन्य एजेंसियों का काम है। इसके साथ विदेशों में हो रही गतिविधियों को भी गंभीरता से लेना होगा। भारत ने लंदन की वारदात में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यदि ब्रिटिश शासन ऐसा करने में विफल रहता है, तो भारत को फिर से विरोध जताना चाहिए। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत निर्णायक दौर में है। वहां भारतीय मूल के प्रधानमंत्री भी हैं। हमारी खुफिया एजेंसियों को ब्रिटिश एजेंसियों के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश भी करनी चाहिए कि कहीं ऐसे प्रदर्शनों के पीछे पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है। अतीत में हम देख चुके हैं कि आइएसआइ द्वारा अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों सहायता दी जाती रही है। आज पाकिस्तान भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वह पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्भर है।

ऐसी स्थिति में वह अगर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की अपरिपक्व नीति अपनाता है, तो उसकी स्थिति और खराब होगी। हाल के दिनों में हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देखा है कि किस प्रकार पाकिस्तानी मंत्रियों ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाये हैं तथा आतंकिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास किया है। विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी और भारतीय मूल के लोग हैं। उन देशों में उनके परिश्रम, कौशल और मेधा की बड़ी प्रतिष्ठा है। उनमें से गिने-चुने लोग ही भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। यदि वे भारतीयों पर या भारत से संबंधित प्रतिष्ठानों पर हमला करते हैं, घृणा का वातावरण पैदा करते हैं तथा भारत में सक्रिय आतंकी व अलगाववादी गुटों को संसाधन मुहैया कराते हैं, तो यह उन देशों की सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों का काम है कि उन पर कार्रवाई करें।

जिन देशों में खालिस्तान समर्थक समूह सक्रिय हैं, उनसे भारत के अच्छे संबंध हैं। वे देश भी आतंकी घटनाओं से पीड़ित हो चुके हैं। हमें उन देशों से भारत विरोधी गुटों से जुड़ी सूचनाओं की मांग करनी चाहिए। यदि इन प्रवृत्तियों को समय रहते नहीं रोका गया, तो प्रवासी भारतीयों के विशाल समुदाय के लिए अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। खालिस्तान समर्थक गुट विदेशों में बसे भारतीयों में आपसी फूट पैदा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह भारत के लिए एकता, अखंडता एवं सुरक्षा से संबंधित मसला है। हमें कूटनीतिक उपायों से विभिन्न देशों को भरोसे में लेना होगा तथा भारतीय प्रवासी समुदाय की एकजुटता को सुनिश्चित करना होगा। पंजाब लंबे समय तक अलगाववाद की आग में झुलसता रहा था और बड़ी संख्या में लोगों की जानें गयीं। वह स्थिति अब दुबारा पैदा नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में राज्य और देश के स्तर पर हमें अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों को जो विदेशों से मदद मिल रही है, उसे बंद करने के लिए हमें विभिन्न सरकारों पर दबाव बढ़ाना होगा तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साथ जोड़ना होगा। जब पंजाब में हिंसा और आतंक का दौर था, तब राज्य और देश में सांप्रदायिक माहौल भी बना था। उस माहौल ने बड़ी संख्या में लोगों की जानें लीं। हत्याओं का सिलसिला देश की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा था। देश और प्रवासी भारतीय समुदाय को सचेत रहना होगा कि उनके बीच संप्रदाय के आधार पर कोई फूट नहीं हो। जो भी ताकतें अमृतपाल और उसके अलगाववादी एजेंडे के पीछे हैं, वे यही चाहती हैं कि भारत समुदायों की आपसी रंजिश और लड़ाई में फंस कर रह जाए।

गांधी आज

चरखा और हाथ करघा

चरखे के बदले सिर्फ हाथ-बुनाई के धंधों को उत्तेजन देना, और मिल के सूत का नहीं, केवल मिल की बुनाई भर का बहिष्कार करना चाहिए यह सुझाव, चरखे के बारे में लोगों में जो गलतफहमी है, उससे पैदा होता है। कारण यह कि- इस विचार को समझने में श्री ग्रेग की पुस्तक से लिया गया नीचे लिखा हिसाब उपयोगी होगा-हाथ-कताई और हाथ-बुनाई के द्वारा एक आदमी जितना सूत कालता और कपड़ा बुनता है उससे मिल में (1926 ई. के हिसाब के अनुसार) कताई आदमी पीछे घंटा 203 से 236 गुना तक और बुनाई 20 गुना अधिक होती है। अर्थात दोनों बराबर-बराबर घंटे काम करें तो सूत की मिल का मजदूर 200 से अधिक कतैयों को और मिल का बुनकर 20 हाथ-बुनकरों को बेकार बनाता है। ऐसे बेकारों का पौना भाग या समय दूसरे धंधों में लगता है। इतनी उदारता से हिसाब करें तो भी 2671 लाख मनुष्यों की तीन आने रोज की मजदूरी का नुकसान होता है। इनके निर्वाह का खर्च यदि विदेशी और स्वदेशी मिलों के कपड़ों पर रखा जाय तो की गज पौने दो आना, और सिर्फ विदेशी कपड़े पर रखें तो छः आना दो पाई कीमत उस कपड़े की बढ़ जाएगी। यदि राष्ट्रीय सरकार इन बेकारों का निर्वाह खर्च कपडे की मिलों से प्रत्यक्ष कर के रूप में वसूल करे तो स्पष्ट हो जाय कि मिल का कपड़ा सस्ता नहीं है। आज इस खर्च को जनता परोक्ष रीति से देती है, इस कारण कपड़े के बाजार भाव में यह हाथ कताई का उद्योग जिस प्रकार सार्वत्रिक हो सकता है उस प्रकार हाथ बुनाई के उद्योग के सार्वत्रिक होने की संभावना नहीं है। चरखा सह उद्योग ही हो सकता है और बुनाई स्वतंत्र उद्योग के रूप में चल सकती है, यह बात उक्त सलाह देनेवालों के ध्यान में नहीं आई। अगर कानून के द्वारा मिल की बुनाई बंद न हो बल्कि जनता के प्रयत्न से ही उसका बहिष्कार करना पड़े तो बुनकरों को मिलों की दया पर ही अवलंबित रहना पड़ेगा। क्योंकि मिलें तो हाथ-बुनाई की प्रतिद्वंद्वनी हैं और दिन-दिन मिलें ही बुनाई का काम अधिक करती जा रही है। यह प्रतिस्पर्द्धा अधिक कड़वी और घातक होती जानेवाली है। इसके विपरीत हाथ-करघा और चरखा दोनों जुड़वाँ भाई-बहन हैं। दोनों एक-दूसरे के बिना जी नहीं सकते। प्रत्येक घर में एक चरखा और थोड़ी आबादीवाले हर एक गाँव में एक करघा, यह आनेवाले युग के विधान का मंत्र है।

बेरोजगारों को मिलेगा 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा, योजना को स्वीकृति प्रदानः मापदंड एवं शर्तें जारी किए गए

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है- पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता। पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष का एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी को ऑफर दिया जाता है, परन्तु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधान सभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। 10,000/- रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।

बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

गोबर खरीदीः श्रीसीमेंट और जिला प्रशासन बलौदाबाजार-भाटापारा के बीच एमओयू

- ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने श्रीसीमेंट प्रतिदिन खरीदेगा 10 मीट्रिक टन गोबर
- एडीशनल फ्यूल रिर्सोसेज के रूप में होगा गोबर का उपयोग

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में श्रीसीमेंट उद्योग और जिला प्रशासन बलौदाबाजार-भाटापारा के बीच एमओयू हुआ। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा विकासखण्ड में स्थापित श्री सीमेंट उद्योग द्वारा गोबर क्रय करने की सहमति दी गई है। कोयले की जगह ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने श्रीसीमेंट प्रतिदिन खरीदेगा 10 मीट्रिक टन गोबर। एडीशनल फ्यूल रिर्सोसेज के रूप में गोबर का भट्टी को गरम करने में कोयले के साथ उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा श्री रजत बंसल और श्री सीमेंट के श्री रवि तिवारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि श्रीसीमेंट के सबसे समीप के गांव चण्डी में गोबर अन्य स्थानों से एकत्र कर कंपनियों को दिया जायेगा। गोबर की पूर्ति सीमेंट उद्योग के 15 किलोमीटर के परिधि वाले 16 गांव से प्रतिदिवस 10 मीट्रिक टन गोबर प्रदाय किया जाएगा। कम्पनी को अब तक 38.8 मीट्रिक टन गोबर प्रदाय किया जा चुका है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 07 गौ-शालाएं हैं, जिसमें 1739 पशुओं को रखा गया है, इनमें 04 सिमगा विकासखण्ड में ही स्थित है जो 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। गौ-शालाओं से भी प्रति दिवस 6 मीट्रिक टन गोबर प्रदाय की संभावना है। जिले में उद्योगों के समीपस्थ लगभग 95 गांव हैं, जिसमें पशुओं की संख्या लगभग 80 हजार है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन की गोबर खरीदी की योजना से प्रभावित होकर गोबर के उपयोग के नए-नए नवाचार सामने आ रहे हैं। गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, दिये और गमले बनाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में अब प्राकृतिक पेंट और बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के श्रीसीमेंट उद्योग ने एडीशनल फ्यूल रिर्सोसेज के रूप में गोबर का उपयोग करने का फैसला किया है।

संक्षिप्त समाचार

महिलाओं के लिए खेल प्रतियोगिता 24 मार्च को

बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में महिलाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग द्वारा 24 मार्च को स्व. बी.आर.यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में महिलाओं के लिए दो आयु वर्गों में प्रतियोगिता रखी गई है। प्रतियोगिता में 40 से कम आयु वर्ग की महिलाएं कबड्डी, खो-खो, रस्साकस्सी, 100 मी. दौड़, व्हालीबॉल, लम्बीकूद में एवं 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिलाएं रस्साकस्सी, कुर्सी दौड़, मटका फोड़, नींबू दौड़, बलून दौड, 400 मी. पैदल चाल, और सुई धागा दौड़ खेल में भाग ले सकेंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने इच्छुक प्रतिभागी खेल एवं युवा कल्याण विभाग में अपना पंजीयन करा सकती है। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार भी विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

आईटीआई के प्रशिक्षणार्थी प्रमाण पत्रों में कर सकेंगे त्रुटि सुधार

बिलासपुर। जिले के शासकीय एवं निजी आईटीआई में सत्र 2014 से 2021 तक अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी अब अपने प्रमाण पत्रों में हुए त्रुटियों जैसे अपना नाम, पिता अथवा माता का नाम, लिंग, आधार, मोबाईल नंबर एवं ईमेल एड्रेस में सुधार एमआईएस पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल में ग्रिवेन्स ऑप्शन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ऑनलाईन त्रुटि सुधार के बाद प्रशिक्षणार्थियों को आईटीआई कोनी के जिला नोडल कार्यालय में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह सुविधा पोर्टल पर ग्रिवेन्स ऑप्शन ओपन रहने तक ही उपलब्ध रहेगी। अधिक जानकारी के लिए जिला नोडल कार्यालय आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी में भी संपर्क कर सकते है।

जलापूर्ति योजनाओं का काम अधूरा छोड़ा, तीन ठेका फर्म हुए ब्लैक लिस्ट

रायपुर। धरसींवा क्षेत्र के गांव में जलापूर्ति योजनाओं का काम अधूरा छोडने वाले तीन ठेका फर्मों को ब्लैक लिस्ट किए जाने की जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने धरसींवा विधाश्क अनिता शर्मा के सवाल के जवाब में दिए। विधायक अनिता शर्मा ने मंत्री से मांग की थी कि विभाग ने इन ठेकेदारों की सुरक्षा निधि राजसात की है क्या उन्हें ब्लैक लिस्ट करेंगे? मंत्री ने जवाब में कहा कि तीनों ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है आगे भी जो ठेकेदार काम अधूरा छोड़ेंगे उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा।

चेट्रीचण्ड्र पर्व पर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों के लिए सामान्य अवकाश घोषित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप 23 मार्च 2023 दिन गुरूवार को चेट्रीचंड्र (चैतीचांद) महोत्सव के लिए राज्य के सभी नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में सामान्य अवकाश रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सामान्य अवकाश की अधिसूचना जारी की गई है। इस दौरान राज्य में सभी बैंक एवं अन्य शासकीय वित्तीय संस्थाएं, कोषालय, उप कोषालय, सहकारी बैंक आदि खुले रहेंगे। नया रायपुर स्थित सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि समस्त शालाओं में 23 मार्च को पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं यथावत् रहेगी। शेष के लिए 23 मार्च चेट्रीचंड्र (चैतीचांद) महोत्सव का अवकाश रहेगा।

छग का नाम रौशन करेंगे अर्पण के मूक-बधिर बच्चे

रायपुर। अर्पण कल्याण समिति द्वारा राजेन्द्रनगर में संचालित अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत मूक-बधिर बच्चों को मूर्ति निर्माण कला सिखाई गई। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा दस दिवसीय पुरातत्वीय प्लास्टर कास्ट प्रतिकृति प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों की हौसला आफजाई के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रभारी महामंत्री सुभाष शर्मा यहां पहुंचे थे। बच्चों द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं की प्रतिकृति को देखकर वे आश्चर्य चकित रह गए। उन्होंने बच्चों की कला व लगन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन बच्चों की कला को और निखारा जाए तो ये छत्तीसगढ़ का नाम दुनिया में रौशन कर सकते हैं। बिना सुने व बिना बोले केवल इशारों की भाषा से समझकर प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिट्टी को जीवंत रूप देना किसी करिश्मा से कम नहीं है। और यह करिश्मा अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल के मूक-बधिर बच्चों ने कर दिखाया है। इनके प्रशिक्षक संजय झरबड़े भी प्रशंसा के पात्र हैं। शर्मा ने स्कूल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने स्कूल की गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

सफलता की राह पर जल जीवन मिशन

दन्तेवाड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अति महत्वपूर्ण नल जल योजना लाई गई है योजना के तहत पानी टंकी निर्माण से लेकर पाइप लाइन विस्तार के साथ सभी घरों में नल का कनेक्शन किया जा रहा है। जिससे इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। विभाग द्वारा ग्रामीणों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध होने से उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। जिले के कुआकोंडा विकासखंड अंतर्गत अरनपुर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम मेंडपाल में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने एवं नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिससे नल जल योजना के तहत ग्राम पंचायतों में लोगों के घरों में नल से जल पहुंचना प्रारंभ हो गया है। इससे गांव के 35 परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है शेष परिवारों तक शीघ्र पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पानी जीवन का अमूल्य हिस्सा है इसके बिना जीवन की कल्पना ही नही की जा सकती एक समय ऐसा भी था जब ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या बनी हुई थी जहां पर लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर मीलो सफर तय कर पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन आज शासन प्रशासन के प्रयास से अब पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल, समूह नल जल योजनाओं को रेट्रोफिटिंग योजनाएं के माध्यम से गांव तक घरेलू नल कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से ऐसे ग्रामीण और सुदूर इलाके, जहां जल की उचित व्यवस्था नहीं है वहां हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की महिलाओं के चेहरे पर पानी को लेकर चिंता की रेखाएं नजर नहीं आएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल की समस्या को दूर किया जा रहा है। और हर घर जल की संकल्पना साकार किया जा रहा है।

शहीदों की शहादत को याद करने इनकलाब शहीदों की शाम का आयोजन आज

भिलाई। 23 मार्च को सेक्टर 5 शहीद पार्क भिलाई में शहीद दिवस मनाया जाएगा। शहीद दिवस के अवसर पर हमारे देश के वीर शहीद जवानों की याद में इनकलाब शहीदों की शाम कार्यक्रम का आयोजन एनएसयूआई दुर्ग के द्वारा किया जा रहा है । इस कार्यक्रम में युवाओं के चहेता और सुप्रसिद्ध कलाकार राजस्थान के सिंगर रैपरिया बालम भिलाई आएंगे। जो इस कार्यक्रम में अपने देशभक्ति गीतों से वीर शहीदों के शहादत की गाथा गाएंगे। उनके सम्मान में सुरीली गीतों की प्रस्तुति देंगे। देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते-हंसते न्यौछावर करने वाले तीन वीर सपूतों का शहीद दिवस है। 23 मार्च यानि क्रांतिकारी वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस। यह दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान का दिन है बल्कि हम सब के लिए वीर सपूतों के बलिदान को नम आंखों से श्रद्धांजलि देना का दिन है। उन अमर क्रांतिकारियों की शहाद को हमारी युवा पीढ़ी कभी भूल ना पाए, सदैव उनकी कुरबारियों को हम याद रखें।

अमृतपाल के समर्थन में कुछ लोगों ने रायपुर में निकाली रैली

रायपुर। राजधानी रायपुर तक पहुंच गई है पंजाब के अमृतपाल सिंह घटनाक्रम की धमक,उस वक्त खबर तेजी से फैली जब तेलीबांध इलाके में कुछ लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर अमृतपाल के समर्थन में बुधवार को रैली निकाल दी। रैली में शामिल लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रायपुर के आप कार्यालय तक पहुंच गए और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ जैसे शांतिप्रिय राज्य में इस प्रकार की रैली निकाले जाने से स्थानीय सिक्ख समाज आश्चर्यचकित है पहले तो वे अनभिज्ञ थे आखिर ये लोग है कौन? लेकिन जब मीडिया में खबर आई तो उन्होने इसकी कड़ी भर्त्सना की है। अब सवाल यह भी सामने आ रहा है कि क्या इन्होने रैली निकाले जाने के लिए पुलिस से अनुमति ली थी और यदि नहीं तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है। उधर अमृतपाल सिंह के समर्थन में उतरे लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमृतपाल पंजाब में नशे के खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन ड्रग्स माफिया को संरक्षण देने के लिए उसे फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने अमृतपाल को आतंकी घोषित करने का दावा किया है। यहां बताना जरूरी होगा कि अमृतपाल फरार है और पंजाब पुलिस तलाश रही है। उनके कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। पंजाब के ताजा हालात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा सत्र के दौरान बयान आया है कि नई सरकार बनने के बाद पंजाब की स्थिति बिगड़ गई है। बहुत परेशानी झेलकर लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुर्बानी के बाद पंजाब शांत था। इस तरह की घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

भारत के भविष्य का निर्धारण हिंद महासागर से जुड़ा है -संजय प्राशर

रायपुर। साइंस कॉलेज, रायपुर के रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ऑनलाइन माध्यम द्वारा मुम्बई से जुड़े कैप्टन संजय पाराशर ने कहा कि हिंद महासागर को भारत किसी भी दशा में हल्के में नहीं ले सकता है। भारत का आयात और निर्यात, मत्स्य उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीधे हिंद महासागर से जुड़े हैं। जो राष्ट्र समुद्र पर अपना दबदबा कायम करेगा, वही राष्ट्र भविष्य का महाशक्ति बनेगा। पुणे से कमोडोर अनंब दास ने समुद्र के नीचे होने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला। संयुक्त अरब अमीरात से प्रोफेसर आई बी सिंह ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंद महासागर पर जब भी भारत का प्रभुत्व कायम रहा है, भारत का स्वतंत्रता अक्षुण रहा है। जब भी विदेशी शक्तियों ने हिंद महासागर में प्रवेश किया है, भारत अपने भूक्षेत्र में भी कमजोर हुआ है। अंतिम वक्ता के रूप में कैप्टन अरिजीत दास ने भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा प्रबंधन पर पीपीटी के माध्यम से विस्तृत वर्णन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर निधि शुक्ला ने किया।

एक तालाब की राजनीतिक हत्या

आशीष सिंह

एक बड़ा ही मजेदार पत्र 1954 में मेरे पितामह त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह को ग्राम सलखन से भेजा गया था। वे उस समय सी.पी. एंड बरार विधान सभा (नागपुर) में नेता प्रतिपक्ष थे। वे प्रजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रायपुर से निर्वाचित हुए थे। उस पत्र में उल्लेख किया गया है कि तालाब निर्माण के कार्य को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि एक दल विशेष को डर था कि यदि तालाब बन गया तो उनका वोट खिसक जाएगा। ध्यान रखने योग्य है कि 1954 में छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था। केंद्र सरकार ने अकाल पीड़ित योजना के अंतर्गत तत्कालीन बिलासपुर जिले के अकलतरा तहसील के सलखन गांव में पनभरिया तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव पारित किया था। परंतु कुछ नेता किस्म के लोगों को वोट-बैंक खिसकने का डर सताने लगा। उन्होंने अपनी पहुंच के दम पर निर्माण कार्य रुकवा दिया। आगे पत्र यथावत दिया जा रहा है-

समाचार विदित हो कि हमारे गांव मौजा सलखन में अकाल पीड़ित योजना के मुताबिक भारत सरकार ने तालाब खुदवाने की प्रस्ताव पास किया है और पी.डब्लू.डी. के आफिसर (ओवरसियर) एम.पी. परासर दिनांक 7.6.54 को तालाब निरक्षण करने आये। उनके साथ गांव के समस्त जनता, कास्तकार, पंच सब थे। उनको हमारे हथनी तालाब और पनभरिया तालाब दिखलाये। अधिक निस्तार, अधिक आपासी देखकर तथा पानी भरने का अच्छा साधन देखकर जनताओं की राय से पनभरिया तालाब को पास कर ता. 8.6.54 को काम शुरु करवा दिये। ता. 8.6.54 से लगाता 13.6.54 तक काम चला। इसी बीच में रंगे कांग्रेसी कहलाने वाले; जैसे दुर्गाप्रसाद मिश्रा, प्रहलाद पांडे, और दोचार व्यक्तियों को मिलाकर सलाह दिये कि गांव में बहुत अधिक बहुमत प्रजा पार्टी की है। तथा तालाब पर काम चलाने के लिए सब कार्यकर्त्ता प्रजा पार्टी के ही आदमी थे।, कांग्रेस की अस्तित्व ही यहां से समाप्त हो जायगी। ऐसा सोच कर वे लोग गांव में दो पार्टी कराने के विचार से उन लोगों ने एक (ऊपर की पंक्तियां नष्ट)

हथनी है उसके नजदीक पर रहने वाले व्यक्तियों से दस्खत करवाये। तथा दुर्गाप्रसाद मिश्रा अपने जीजा जगदीशचंद तिवारी जो गांव पटवारी है उससे हथनी तालाब का रकबा लेकर उस दरखास्त में दर्ज किये और दसखखत करने वाले लोगों से बोले कि बड़ा तालाब पास हुआ है। हथनी तालाब का रकबा बड़ा है। हथनी तालाब खुदवाना चाहिए ऐसा कहकर दरखास्त को लेकर लखेश्वर पालीवाल एम.एल.ए. के पास नैला आये। वोट बिगड़ जाने का हाल सुनाया और कहा कि ए.डी.सी. जांजगीर से मिलकर हथनी तालाब को पास करवावो। उसमें काम शुरु हो जावेगा तो हम लोग खुदवा रहे हैं ऐसा कहकर अपने नाम व कांग्रेस वालों का पैसा है कहकर जनता को बहकावे में डाल हम अपना वोट बढ़ा लेंगे। और हमारी भारी ताकत बढ़ जावेगी इसी विचार से वे लोग ए.डी.सी. से मिले। और इसी बीच में रामकृष्ण राठौर एम.एल.ए. सलखन आये। उनके पास एक दरखास्त था। उसने कहा कि हथनी का रकबा बड़ा है। और नागपुर से हथनी पास हुआ है। पनभरिया (की) जो खोदाई हो रही है। वह नाजयज है। हम सलखन के कास्तकार उनसे कहे कि आप यहां फूट मत करिये। आप और गांव के पंच जिसे आप पसंद करे और पटवारी को भी ले जा सक्ते हैं। दोनों तालाबों को देख लें और भी गांव के समस्त तालाबों को देख ले इसके बाद जैसी आप लोगों की विचार में

खुदाई (आगे की पंक्ति नष्ट) राठौर जी किसी भी बात पर सहमत (आगे की पंक्ति नष्ट) सामने भी जनता की बहुमत अधिक आपासी, अधिक निस्तार पनभरिया तालाब में पाई गई। लेकिन इस विषय पर उनने तनिक भी ध्यान न दिया। उनने कोरा जवाब दिया। हमारा राज्य है। हमने पैसा निकलवाया है। हम तथा हमारे कांग्रेसी भाई जिस किसी को भी खुदवा सक्ते हैं। चाहे भले ही रुपया का दुरुपयोग क्यों न हो चाहे यों ही फेक क्यों न दिया जावे ऐसा उनने कहा और दूसरे दिन हथनी तालाब में ओवरसियर को बुलाकर काम करवाना शुरु करवा दिये।

रामकृष्ण राठौर, लखेश्वर पालीवाल, ए.डी.सी.जांजगीर से मिलकर पनभरिया तालाब को बंद करवा दिये। यह घटना देखकर गांव के जनता व्याकुल हो गये। गांव के मुख्य मुख्य कास्तकारों ने करीब 11/2 सौ से अधिक एक अर्जी बनाकर ए.डी.सी. जांजगीर में दिये। एक जिले साहब को दिये। तथा तार द्वारा दिगविजय सिंह वकील साहब ने जिले साहब से उत्तर मांगे कि सलखन तालाब खुदवाने का जो पास हुआ है। उसकी रकबा कितना है उत्तर मिला बड़ा तालाब पास हुआ है। नम्बर रकबा नहीं है। और ए.डी.सी. से भी जवाब मिला। एक अर्जी वकील साहब के द्वारा ए.डी.सी. साहब को दिये। उनने कहा कि

(सामने के शब्द नष्ट) साहब से शाम को हमारे गांव आने के पहले राठौर और लखू इस बाबत मिल चुके थे। मूले साहब आये बयान हुआ नक्सा पटवारी ने बनाकर दिया था लेकिन काम बयान और नक्सा के विपरीत हुआ। साथ ही साथ पनभरिया का मौका देखने ही नहीं गये। ता. 30.6 को जब लखेश्वर पालीवाल आया तो बोल गया कि मूले साहब कर क्या सकता था। मैं तो सब समझा बुझा दिया था। अगर इधर उधर गड़बड़ करता तो होलिया तंत्र हो जाता?। जब बड़ा तालाब पास हुआ है। तो लंकेटर तालाब सबसे बड़ा है। (चार, फुलवारी, और हथनी तिनो मिलाकर रकबा इनके कागजात में जालसाजी भरा है।) अगर इसी प्रकार से मेलकर लेते हैं तो पनभरिया का तो अंदाजन 40 एकड़ का बड़ा बांध तैयार हो सक्ता है।)

दिनों दिन ये कांग्रेसी बड़ा अत्याचार कर रहे हैं यहां तक कि नीचला पर उतारू हुए हैं कि जब हमारे पार्टी के कोई भी आदमी बर्ताव ग्राम सेवक, शिक्षकगणों से करते हैं। तो नौकरी से अलग कर देने की धमकी देते हैं। हमारी पार्टी में गरीब मजदूर बहुत हैं उन्हें हथनी तालाब में काम नहीं किया (दिया) जा रहा है ले भी लेते हैं तो कांग्रेस को मदद देने के लिए वोट देने के लिए कहा खिला रहे हैं। गांव में न्याय होना पंचायत होना खेती किसानी का प्रबंध होना सब बंद हो गया है। अगर गांव का वातावरव (वातावरण) इसी प्रकार से आगे रहेगी तो हो सकता है कि एक बड़ा मामला के रूप में न हो जावे।

पत्र द्वरा वकील साहब रतन सिंह जी दिगविजय सिंह महावीर शर्मा जी को समाचार भेजे थे कि आकर तालाबों का रकबा का मौका देख ले। और आगे क्या करना है हम लोगों को उचित सलाह देवे लेकिन उन लोगों का हम लोगों को कोई उत्तर नहीं मिला। वे इस विषय में दिलचस्पी नहीं ले रहे है। हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विषय पर अगर सरकार से लडने योग मामला होगा तो अवश्य लड़ेंगे। अगर आप असेम्बली में चर्चा करने लायक विषय होगा तो जरूर चर्चा करेंगे और हो सकेगा तो जांजगीर के प्रजा समाज- (आगे की पंक्तियां पृष्ठ के ऊपरी हिस्से पर उलटा लिखा हुआ है। ऊपर लिखा आरंभिक अक्षर नष्ट।) पनभरिया तालाब पर ही काम शुरू करवाने की दया करेंगे। (द्वितीय पंक्ति के अक्षर नष्ट) रकबा 13.55 ए. है।

संक्षिप्त खबरें

विश्व जल दिवस पर मुख्यमंत्री का संदेश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि जल जीवन का आधार है। विश्व जल दिवस के मौके पर सभी के लिए और भी जरूरी हो गया है कि जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध हों। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ तालाबों, नदियों का प्रदेश है। सही देखरेख और जागरूकता से हम इन जल स्त्रोतों का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार नरवा कार्यक्रम के तहत् इन जल स्त्रोतों के संवर्धन का प्रयास कर रही है, मगर इसके लिए जन समुदाय की सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है। सभी नागरिकों से आग्रह है कि हमारे धरोहर तालाब, नदियों और जल स्त्रोतों को बचाने के लिए स्वयमेव पहल करें और नई पीढ़ी को भी इसके लिए प्रेरित करें।

एक अथक जननेता पुस्तक का विमोचन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के जीवन पर लिखी गई-एक अथक जननेता-पुस्तक का विमोचन आज विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, स्वास्थय मंत्री टीएस सिंहदेव अन्य मंत्रियों व विधायकों की उपस्थिति मे किया गया। डा. सुरेश शुक्ला द्वारा सत्यनारायण शर्मा के जीवन के अनेक ऐसे प्रसंगों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए थे। सत्तू भैया के नाम से जाने वाले जननेता के जीवन में आए अनेक उतार चढ़ाव का बखूबी इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। विमोचन अवसर पर लेखक डा. सुरेश शुक्ला, पंकज शर्मा, महेश शर्मा, डा. शकील, सहदेव व्यवहार, घनश्याम क्षत्री, जीतू भारती, मो. अशरफ, तिरथ साहू, गोलू मिश्रा, अरूण राजूसेन, अमजद भाई, मोहन साहू एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

विधानसभा में अनिता शर्मा ने उठाया जल जीवन मिशन का मुद्दा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस सदस्य अनीता योगेंद्र शर्मा ने जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाते हुए पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार से सवाल किया कि वर्ष 2021- 22 वर्ष 2022- 23 जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायपुर जिले में कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि के वर्क आर्डर जारी किए गए हैं? विधानसभा वार जानकारी दें। इस पर मंत्री गुरु रूद्र कुमार ने जवाब में कहा कि जिलेवार बजट का आवंटन नहीं किया जाता। जिलेवार खर्च के लिए आहरण सीमा जारी की जाती है। रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत 832400 लाख वर्ष 22- 23 में 17539. 60 लाख की राशि की आहरण सीमा जारी की गई। कुल 46533. 55 लाख के वर्क आर्डर जारी किए गए हैं।

धर्मजीत सिंह ने उठाया खुड़िया प्रवेश द्वार का मामला

प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ने अचानकमार टाइगर रिजर्व के लिए ग्राम खुड़िया में प्रवेश द्वार खोले जाने संबंधी जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि खुड़िया में टाइगर रिजर्व प्रवेश द्वार खोला जाना है तो कब तक इसे खोला जाएगा? उनके सवाल पर वन मंत्री

मोहम्मद अकबर ने कहा कि अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली और बिलासपुर जिला अंतर्गत स्थित है। टाइगर रिजर्व के लिए खुड़िया में प्रवेश द्वार खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। इस पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि खुड़िया पर्यटन स्थल है। प्रवेश द्वार खोला जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस प्रस्ताव पर स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार से गेट खोलने की अनुमति नहीं है। तब धर्मजीत सिंह ने कहा कि खुड़िया नहीं तो अन्य गांव में गेट खोला जा सकता है। आवागमन के लिए साधन होगा। अन्य क्षेत्र में गेट खोला जा सकता है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस पर कहा कि इसका परीक्षण करा लिया जाएगा।

शिवरतन ने उठाया मुआवजे का मुद्दा

भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने छुई खदान उदयपुर दनिया रोड की जमीन के अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का ध्यान आकर्षित कराया शिवरतन शर्मा के अनुसार क्षेत्र के 74 परिवार पट्टा धारी हैं, जिन्हें अब तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

शिवरतन शर्मा के ध्यानाकर्षण पर राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि संबंधित क्षेत्र में प्रभावितों के लिए सरकार भुगतान की व्यवस्था कर रही है। 219 खातेदारों में से 149 खातेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। इनमें आज खातेदारों को मुआवजा राशि भुगतान कर दी गई है। इन्हें 19 लाख से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। 12 खातेदारों को जल्द मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। 134 खातेदार ऐसे हैं जिनके भुगतान की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। 77 खातेदारों का नाम जोड़ा गया है। निर्माण के एवज में भुगतान के रूप में 55000000 की राशि दी गई है।

मंत्री मोहम्मद अकबर से संबंधित विभागों की वर्ष 2023-24 के लिए 4482 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे पारित

वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन तथा विधि-विधायी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने विभागों से संबंधित 4 हजार 481 करोड़ 80 लाख रूपए की प्रस्तुत अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई। इनमें न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 707 करोड़ 19 लाख रूपए, परिवहन विभाग के लिए 124 करोड़ 75 लाख रूपए, आवास एवं पर्यावरण विभाग के लिए 955 करोड़ 25 लाख रूपए और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 2 हजार 694 करोड़ रूपए की राशि शामिल हैं। वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री अकबर द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों में राज्य में वनों के संरक्षण तथा संवर्धन सहित वनवासियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही इसमें स्थानीय वनवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके आय के साधन में वृद्धि के लिए पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। इसके तहत वर्ष 2023-24 के बजट में आज 21 मार्च को विश्ववानिकी दिवस के अवसर पर शुरूआत हुई राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ प्रतीकात्मक वनरोपण निधि से व्यय के लिए 1000 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में वन विभाग अंतर्गत ईमारती लकड़ी के व्यापार में वृद्धि करने के लिए 166 करोड़, पर्यावरण वानिकी हेतु 33 करोड़, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास के लिए 29 करोड़ रूपए तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों के लिए 41 करोड़ 46 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में भू-जल तथा जल संरक्षण कार्यों के लिए 280 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में कैम्पा मद अंतर्गत वनांचल में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत बढ़े पैमाने पर भू-जल संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे है। इसके तहत वनांचल में चार वर्षों के दौरान 6 हजार 395 नालों में डेढ़ करोड़ से अधिक संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इससे लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार होगा। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में अब तक वन क्षेत्रों में बड़े तादाद में वन अधिकार मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई है।

डॉ. रमन ने तेंदूपत्ता पर सरकार को घेरा, स्थगन अग्राह्य

लखमा ने कहा आदिवासी को वनवासी ना कहें धर्मजीत ने कहा बजट में मुख्यमंत्री ने खुद भी लिखा है वनवासी

सदन में तेंदूपत्ता में वनवासियों की आय में पहले की तुलना में कमी का मामला पूर्व मुख्य मंत्री डॉ.रमनसिंह ने शून्य काल में उठाते हुए मुख्य मंत्री भूपेश बघेल से पूछा कि आपने दर बढ़ाया उसके बावजूद आय में कमी हो रही है, इसका कारण क्या है? आपने चरण पादुका योजना बंद क्यों की? तोड़ाई के समय में कमी क्यों की ? रमनसिंह ने कहा हमने इस मुद्दे पर स्थगन दिया है ग्राह्य कर चर्चा कराई जाए। सभापति धनेंद्र साहू ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्थगन को अग्राह्य करने की घोषणा के साथ ही विपक्ष के सदस्य हल्ला गुल्ला करने लगे। सभापति ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

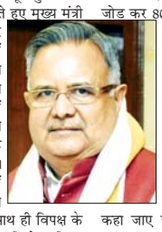

डॉ.रमन सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के दौर में तेंदूपत्ता 350 रु.से बढा कर 2500 किया गया। वनवासियों के पैरों में कांटे ना चुभे इस लिए हमने चरण पादुका योजना बनाई, आपने बंद कर दी। आप कह रहे हैं कि आपने 4000 रु. मानक बोरा खरीदी की है। हमारे समय प्रोत्साहन राशि जोड कर 8000 रु तक भुगतान वनवासी को प्राप्त होता था। अब हाल ये हैं कि यह आय घट कर मात्र 6800 रु. हो गई है। ये क्यों व कैसे हुआ? हमारे समय 20 से 30 दिन पत्ता तोड़ाई होती थी। आपने उसे 2-4 दिन कर दिया है। हम जो प्रोत्साहन पारिश्रमिक देते थे , वह बंद हो गया है। मंत्री कवासी लखमा ने बीच बीच में व्यवधान करते हुए अपनी बात कहना शुरू किया, उन्होंने कहा कि आदिवासियों को वनवासी ना कहा जाए यह आदिवासियों का अपमान है,हम आज सब जगह रहते हैं, सिर्फ वनवासी नहीं हैं। धर्मजीत सिंह ने इस पर कहा कि बजट में मुख्य मंत्री ने भी वनवासी लिखा है। आप उनसे पूछने की हिम्मत दिखाओ ना। अजय चंद्राकर ने पूछा कि वनवासियों की आय में कमी क्यों हुई ? पैसा कहां जा रहा है? कारण क्या है ? लखमा ने कहा कि आदिवासियों का बीमा होता था, केंद्र सरकार ने बंद क्यों किया? विपक्षी भाजपा सदस्यों ने लखमा द्वारा बार बार शून्य काल में खड़े होकर बाधा पहुंचाने की बात उठाते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री देखें। हल्ला गुल्ला होने पर मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि रमन सिंह 15 साल मुख्य मंत्री रहे हैं।

यह तो जानते ही होंगें की शून्यकाल में भाषण नहीं करते आप खुद भाषण कर रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि हम प्रोत्साहन राशि 749 करोड़ देते थे आप सिर्फ 110 करोड़ दे रहे हैं। ये आदिवासी विरोधी सरकार है। सभापति धनेंद्र साहू ने स्थगन की सूचना उन्होंने विचार कर अग्राह्य कर दी। विपक्षी सदस्य इस पर पर हल्ला गुल्ला व नारेबाजी करने लगे।

सभापति ने 5 मिनट सदन की कार्यवाही स्थगित करने के साथ ही मुद्दा समाप्त उठा। स्थगन शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, अजय चंद्राकर, के.के.बांधी, धरमलाल कौशिक,बृजमोहन अग्रवाल,रजनीश सिंह ने भी हिस्सा लिया।

संविदाकर्मियों- दैवेभो के नियमितिकरण पर मुख्यमंत्री बोले - नियमानुसार की जा रही कार्यवाही

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले ने संविदा कर्मियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियो के नियमितीकरण का मामला उठाया। जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि नियमितीकरण के लिए विधिवत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमितिकरण करने के संबंध में शासन ने प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी ली जायेगी। इस दौरान 47 विभागों से प्राप्त हुई है।

नियमितिकरण समिति की दूसरी बैठक 16 अगस्त 2022 को हुई थी। बैठक में 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी। समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित पांच बिन्दुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है, उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है? 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। समिति द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंसानुसार समस्त विभागों से जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है। नियमितीकरण के लिए विधिवत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोदी सरकार की लापरवाही से मेहुल चोकसे का रेडकार्नर नोटिस रद्द हुआ- मरकाम

रायपुर। भगोड़े मेहुल चोकसे के रेड कार्नर नोटिस रद्द होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अडानी के घोटाले पर पर्दा डालने के लिये संसद में चर्चा नहीं कराने वाली तथा विपक्षी दलों के द्वारा अडानी के घोटाले का संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग ठुकराने वाली मोदी सरकार ने अब अपने एक और मित्र मेहुल चोकसे को भी कानून के सिकंजे से बचाने तथा भारत में गिरफ्तार करके लाने की संभावनाओं को बंद करवा दिया गया। मोदी सरकार की ईडी-सीबीआई मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल को पर्याप्त सबूत नहीं दे पायी इसलिए इंटरपोल ने मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को रद्द कर दिया। अभी तो मेहुल चोकसे के बच निकलने के रास्ते बनाये गये है। यह तय है कि निकट भविष्य में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे मित्रों को बचाने के रास्ते मोदी सरकार खोजेगी। भारत सरकार और सीबीआई ने मजबूती से अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी इंटरपोल के समक्ष मेहुल चोकसे के खिलाफ पक्ष रखा होता तो उसका रेड कार्नर नोटिस रद्द नहीं होता यह मोदी सरकार द्वारा अपराधी को राहत देने के लिये लापरवाही बरती गयी।

चिकित्सा पाठ्यक्रम के संचालन का काम निजी विवि को देना अनेक विसंगतियों को जन्म देगा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक डॉ. विमल चोपड़ा ने कहा है कि आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में चिकित्सा पाठ्यक्रम के संचालन का काम अब निजी विश्वविद्यालयों को दिया जाना अनेक विसंगतियों को जन्म देगा। डॉ. चोपड़ा ने कहा कि आज पैरामेडिकल कोर्स का संचालन निजी विश्वविद्यालयों को सौंपे जाने के बाद भविष्य में संपूर्ण चिकित्सा पाठ्यक्रम के संचालन की मांग निजी विश्वविद्यालय करने लगेंगे जिससे चिकित्सा पाठ्यक्रम के संचालन में विश्वसनीयता का संकट तो उत्पन्न होगा ही, साथ ही निजी विश्वविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम के संचालन में गिरावट की आशंकाएँ प्रबल होंगी। इस संबंध में सोमवार को हुई एक बैठक में डॉ. चोपड़ा ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। डॉ. चोपड़ा ने कहा कि चिकित्सा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन आयुष विश्वविद्यालय द्वारा अच्छे ढंग से किया जा रहा है और चूँकि चिकित्सा पाठ्यक्रम स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है इसलिए इसमें किसी तरह का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा। प्रदेश सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेकर अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि आयुष विश्वविद्यालय की गरिमा बरकरार रह सके और स्वार्थी तत्वों के इरादों को नियंत्रित किया जा सके।

मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का किया विस्तार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण के निर्देशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना को देशभर में जनता तक निचले स्तर में पहुंचाने के लिए गांव-गांव चलो घर-घर चलो अभियान 6 से 14 अप्रैल तक देश भर में चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में 6 से 14 अप्रैल तक प्रदेश जिला और मंडल में अभियान चलाने हेतु भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा के निर्देश पर आज भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राकेश चंद्राकर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में किया गया। बैठक में श्री चंद्राकर ने बताया कि गांव गांव चलो घर-घर चलो अभियान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक जनता के बीच निचले स्तर में पहुंचाने अभियान चलाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज बैठक के दौरान गांव गांव चलो घर-घर चलो अभियान में कार्य का विभाजन किया और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों को कार्यक्रम के लिए नई जिम्मेदारी दी गई है। इसमें राकेश चंद्राकर को दुर्ग संभाग प्रभारी, देवदत्त साहू रायपुर संभाग प्रभारी, निर्देश दीवान बस्तर संभाग, दिलेंद्र कौशिल बिलासपुर संभाग, मनोज गुप्ता सरगुजा संभाग प्रभारी बनाया गया है।

विमान हेलीकाप्टर एवं चार्टर विमान में हुए व्यय को लेकर डॉ. बांधी ने मामला उठाया

रायपुर। डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री से जानना चाहा था कि छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा फरवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान शासकीय विमान एवं हेलीकाप्टर तथा चार्टर हेलीकाप्टर एवं विमान सेवा हेतु कितनी राशि खर्च की गई।

उन्होंने यह भी जानकारी चाही कि छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा क्या पायलट भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को नियुक्ति में वरीयता देने हेतु प्रावधान है और क्या साक्षात्कार में छत्तीसगढ़ मूलनिवासी के लिए कोई अतिरिक्त अंक सुनिश्चित है। विधायक के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विस्तृत जानकारी दी उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा प्रश्न अवधि फरवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान शासकीय विमान पर रू 8,01,40,552/- (आठ करोड़ एक लाख चालीस हजार पांच सौ बावन) एवं शासकीय हेलीकाप्टर पर रू 91,25,582/- (इन्क्यानबे लाख पच्चीस हजार पांच सौ बयासी) तथा चार्टर हेलीकाप्टर के लिये रू 61,30,41,143/- (इकसठ करोड़ तीस लाख इकतालीस हजार एक सौ तिरालीस) एवं विमान सेवा हेतु रू 19,57,84,074/- (उन्नीस करोड़ संतावन लाख चौरासी हजार चौहत्तर) खर्च की गई। विधायक द्वारा पायलट नियुक्ति के प्रक्रिया के सम्बंध में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी

अमृत मिशनः मोदी सरकार ने रायपुर को दिए 540 करोड़ पर अभी तक काम अधूरा -बृजमोहन

रायपुर। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत मिशन योजना में प्रदेश की कांग्रेस सरकार घोर लापरवाही बरत रही है। काम में प्रगति दिख नहीं रही है जनता तक पानी पहुंचाने मोदी सरकार सैकड़ों करोड़ दे रही है और यह भूपेश बघेल की सरकार पैसे तो सरकारी खजाने में रख रही है काम नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यह आरोप ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से लगाया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन दिसंबर 2022 तक राजधानी रायपुर में पूरा नहीं हो पाया है। टेंडर प्राप्त करने वाले और क्रियान्वयन करने वाले तक की मॉनिटरिंग आज नहीं हो रही है। सड़कों को खोदकर महीनों तक पाइप लाइन नहीं बिछाई जा रही, जिसके चलते वातावरण धूलमय हो रहा है लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 11 छोटे शहरों कस्बों में नई पानी पाइप लाइन बिछाने के लिए अमृत मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी इसके लिए 540 करोड़ का फंड स्वीकृत हुआ है जिन 11 कस्बों में प्रोजेक्ट रखा गया है।

भेजरीपदर हिंसा का मामला ध्यानाकर्षण के जरिये विधानसभा में उठाया जाएगा - भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी भेजरीपदर की हिंसा का मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये उठाएगी। भेजरीपदर पहुंची भाजपा की जांच समिति के सदस्य वरिष्ठ भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने आदिवासियों को यह भरोसा दिलाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव द्वारा भेजरीपदर मामले की जांच हेतु गठित 06 सदस्यीय जांच समिति ने भेजरीपदर पहुंचकर घटनास्थल पर सभी बिन्दुओं पर ग्रामीणों से चर्चा की। समिति शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन भाजपा प्रदेश इकाई को सौंपेगी। प्रदेश भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री श्री कंवर ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आदिवासियों की सुरक्षा के मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि अपने राजनीतिक संरक्षण में धर्मांतरण का घातक एजेंडा चला रही प्रदेश की बघेल सरकार पहले नारायणपुर और अब भेजरीपदर, दो-दो जगह बुरी तरह विफल हुई है। श्री कंवर ने कहा कि धर्मांतरण कराने वाले और धर्मांतरित लोगों द्वारा मूल आदिवासियों के साथ-साथ पुलिस पर भी हमला बोलकर हिंसा का तांडव मचाया गया, लेकिन शासन-प्रशासन अब भी खामोशी ओढ़े बैठा है। घटनाक्रम से जुड़े तमाम बिन्दुओं का तथ्यपरक विश्लेषण करने पहुंची समिति के समक्ष भारी संख्या में आदिवासियों ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि धर्मांतरण कराने और करने वालों ने हिंसा की और पुलिस पर हमला किया। घटना स्थल पर समिति के समक्ष हमले में बुरी तरह जख्मी आदिवासी भी उपस्थित थे। श्री कंवर ने आश्चर्य व्यक्त किया कि हिंसा के इस तांडव के बावजूद शासन-प्रशासन के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यंग इंडिया के बोल से युवाओं को मिलेगा राजनैतिक मंच -मोहन मरकाम

युवा कांग्रेस के जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रवक्ताओं के चयन के कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल, सीजन-3 की हुई शुरुआत

रायपुर। भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठन में युवा प्रवक्ताओं के चयन के लिए यंग इंडिया के बोल सीजन-3 की शुरुआत कर दी है, इसी तारतम्य में आज राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम की लॉचिंग की गई, इस प्रतियोगिता से चयन किए गए लोगों को जिला व राज्य स्तर पर प्रवक्ता पद के रुप में नियुक्त किया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, संचार विभाग चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला, भारतीय युवा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुबोध हरितवाल, यंग इंडिया बोल के छत्तीसगढ़ प्रभारी आर्यन शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर देश के युवाओं को अवसर दे रही है, यंग इंडिया के बोल के जरिए देश की युवा आवाज को एक राजनीतिक मंच मिलेगा, जिसके जरिए वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की सोच रही है कि

युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो, यह कार्यक्रम उनकी सोच को साकार कर रहा है, लगातार देश भर से मुखर प्रवक्ता हमारे मंच के माध्यम से सामने आ रहे हैं और अलोकतांत्रिक मोदी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुबोध ने आगे कहा कि आज हम ऐसे दौर में जी रहे है जो किसी भी विषय पर अपनी बात रखने की आजादी खत्म होती जा रही है, खासकर सरकार के खिलाफ, ऐसे में यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम, देश भर के युवाओं को ताकत प्रदान करता है जिसमें वे खुलकर समाज के सामने अपनी बात को रखते हैं।

युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि यंग इंडिया के बोल युवाओं का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है, जहां विचारों को व्यक्त करने का मंच मिलता है, आज देश में आपातकाल जैसे हालात बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र की सरकार द्वारा युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, मोदी म्यूट तंत्र में जहां-जहां भाजपा एक माइक बंद करने का प्रयास कर रही है, वहा युवा कांग्रेस इस कार्यक्रम से युवाओं को लाखों माइक देगी।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ प्रभारी आर्यन शर्मा ने बताया कि यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के जरिए भारतीय युवा कांग्रेस युवाओं से प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन मंगवाता है, उसके बाद भाषण व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, व अंको के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाता है। प्रतियोगिता का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी, प्रादेशिक व स्थानीय भाषाओं में होगा, यंग इंडिया के बोल सीजन 3 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल तक लिए जाएगे जिसमें 18 से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा आवेदन कर सकते है। इसके बाद प्रतिभागियों को जिला व राज्य स्तर तक अगले चरण के लिए चयन किया जाएगा। फाइनल प्रतियोगिता जून माह के अंत मे दिल्ली मे आयोजित कि जाएगी, यह प्रतियोगिता पूर्णतः निशुल्क है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष चकेश्वर गड़पाले, महासचिव भावेश शुक्ला, अनिमेश सिंह, सोशल मीडिया क्नवेयर शान मोहम्मद सैफी उपस्थित रहे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.